As far as our House is concerned, there is nothing against his making it here. Since it is convenient, since we adjourn at 5 and they adjourn at 6, it is better that the Prime Minister makes it here at 5 o'clock.

THE DEPUTY CHAIRMAN. At what time the statement will be made in the other House?

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): Madam, the Prime Minister should not take the plea that since we are not sitting till 6 o'clock he is not making it here.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have just heard it and I will find out.

SHRI BHUPESH GUPTA: But we accept in principle that the statement will be made in this House before the House adjourns for the day.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kapoor.

THE APPROPRIATION (No. 2) BILL, 1965—*continued*

श्री गिरिराज किशोर कपूर (मध्य प्रदेश) उपसभापति महोदया, आज जब हम अप्रोप्रियेशन बिल पर चर्चा कर रहे हैं तो सब मे पहले हमे यह देखना होगा कि हमारे देश की अर्थ व्यवस्था देश की हर परिस्थिति को पूरा करने मे समर्थ है भी या नही ? साथ ही साथ हमको यह भी देखना होगा कि आज देश मे जो एक भयानक सकट आ कर पडा है--पाकिस्तान ने सीमा पर हमला किया है, चीन अपनी फौजो को लेकर, जो उसने सन् १९६२ मे हमला किया था, उससे कई गुना तादाद मे फौजी शक्ति के साथ हमारे ऊपर हमला करने के लिये इरादे कर रहा है देश के अन्दर नागालैंड भी एक तरफ शोर मचा रहा है-- जहा इतनी समस्याए हो वहा सरकार चीजो के दाम नीचे लाने मे अब तक भी समर्थ नही हो सकी है । कुछ दिन पहले चीजो के दाम कुछ गिर रहे थे । हमारे सुब्रह्मण्यम साहब कहते है कि देश मे अन्न की स्थिति बहुत अच्छी है, उन्हे सतोष है । हमारे अर्थ मत्री कहते है देश की अर्थ व्यवस्था बहुत अच्छी है, उन्हे भी उससे सतोष है । सरकार कहती है देश की सुरक्षा की परिस्थिति बिगड रही है, सरकार को भी सतोष है । उधर जनता का बुरा हाल है । टैक्सो के मारे जनता की कमर टूट रही है, महगाई चरम सीमा पर पहुच चुकी है । आखिर गलती क्या है, हमे इस सबध मे अपनी गलती को ढूढना चाहिये ।

जब कोई बीमार पडता है और योग्य डाक्टर के पास जाता है तो योग्य डाक्टर बीमारी के कारण को ढूढता है और अगर कारण मिल गया, तो दवा असर कर जाती है, मर्ज चला जाता है, मरीज अच्छा हो जाता है । बिना कारण ढूढे यदि कीमती से कीमती इजेक्शन दे दिये जाय तो होता यह है कि मर्ज तो जाता नही मरीज चला जाता है । इसलिये आज देश की इस भीषण परिस्थिति मे शाति के साथ सोचना चाहिये कि गलती कहा है । आज जनता कहती है . क्या हमने आजादी इसके लिये ली थी, कि आजादी के बाद हमको यह दिन देखने पड़ेंगे । देश की सीमाए छोटी होती चली जा रही है, सरकार ने जनता को जगाया है। सन् १९६२ मे जब चीन ने हमला किया तब हमारे प्रधान मत्री ने देश की जो असली हालत थी वह रख दी हमारे पास सेना नही है, हमारे पास पैसा नही है, हमारे पास आधुनिक हथियार नही है । और देश की जनता ने प्राइम मिनिस्टर के कहते ही धन दिया सीना दिया, बहिनो ने सोहाग चिन्ह उतार कर दिया, सारा देश सरकार के पीछे हो गया । तो अब सरकार ही आगे न बढे, तो देश क्या करे । आज भी वही स्थिति है । सरकार पूरे देश से आज भी चाहती है पूरा सहयोग दे । इस भीषण परिस्थिति मे देश सहयोग देगा । और देश का सहयोग देने पर भी

[श्री गिरिराज किशोर कपूर]

यदि सरकार आगे न बढे तो फिर इसमे देश क्या करेगा ? एक छोटी सी मामूली बात है । जो चीजे हम लडाई के मैदान मे नही जीत सकते, उसको कान सा पागल होगा जो मेज पर बैठ कर, बात करके, देगा । पाकिस्तान ने हमला कर दिया, वह हमारी कच्छ की सीमा के आठ मील अन्दर घुस आया, और अभी हमने हमले को रोका ही है, हमने हमले का जबाब नही दिया, और सुलह की बातचीत होनी शुरू हो गई । आखिर इस सुलह की बातचीत से हमारे सिपाहियो के मनोबल का क्या हाल होगा, जनता क्या सोचेगी ? हम कितने अपमानित होगे ? और जब पूरे देश की जनता, और तमाम देश के विरोधी दल कहते है आप मुकाबला कीजिए--अगर पाकिस्तान या चीन जब चाहे तब, जहा चाहे वहा हमला कर दे, अपनी खुशी से चला जाए, जब चाहे अपनी खुशी से वापस चला जाय और ऐसा करके दुनिया मे उनका कुछ बिगाड नही हो सकता--तो क्या कारण है कि जब हम रोज इतने अपमानित हो रहे है, तो हमारी सरकार भी कुछ सेन्टर्स ढूढ कर वहा उसका जबाब क्यो नही देती, जब कि देश की पूरी जनता उसके साथ है ? इतना ही नही, देश मे कुछ और खतरे नजर आते है । अभी तीन, चार रोज पहले, असम मे एक रेलवे लाइन उखाड दी गई थी । आखिर सरकार जागती क्यो नही ? पहले सरकार कबूल नही करती थी कि देश मे पचमागी है । मगर परिस्थिति सब कबूल करवा देती है । सत्य ज्यादा दिन तक छिप कर नही रह सकता और सरकार को यह कबूल करना पडा कि देश मे हजारो की तादाद मे नही लाखो की तादाद मे पचमागी है । फिर देश की सुरक्षा के लिये फौजे तो लडाई के मैदान मे लडेगी तो गावो मे कौन मा बहिनो की सुरक्षा करेगा ? इस तोड फोड की कार्यवाही मे कौन किसकी रक्षा करेगा ?

सरकार को कहा गया कि जितनी अपनी सीमा है वहा के रहने वालो को आप मिलिटरी ट्रेनिग दीजिए, भारत के हर नोजवान को आप मिलिटरी ट्रेनिग दीजिए ताकि हम अपनी रक्षा कर सके, मगर सरकार बात को मानने को तैयार नही है । तो प्रजातत्र, मगर प्रजातत्र की आड मे एकतत्रवाद चल रहा है । आप कहेगे, यह कैसे कहते है ? पहली पचवर्षीय योजना बनी । विरोधी दल ने चिल्लाया कि यह योजना गलत है, यह कृषि प्रधान देश है । सरकार से कहा गया कि हजूर, पहले अपने गावो का श्रृंगार कर लीजिये, बडे बडे शहरो को बाद मे देख लेगे, अगर अस्सी फी सदी गावो का श्रृगार हो गया, गाव मे कुटीर उद्योग ग्रामोद्योग हो गए, हर एक गाव अपने आप आप को सपोर्ट करने के लिये क्षम्य हो गया, तो देश अपने आप सुधर जायेगा । बात नही मानी गई, वैसी की वैसी योजना लाद दी गई और योजना लादने के बाद यह भी घोषणा कर दी गई कि पहली पचवर्षीय योजना सफल हो गई, अन्न इतना हो गया कि अब हमे बाहर से अन्न नही मगाना पडेगा, अब तो हम बाहर अन्न भेजेगे, हम इतने समर्थ हो गये है । और परिणाम क्या निकला कि देश के किसान ने कहा कि अन्न इतना हो गया, अब हम अन्न को बो कर क्या करेगे ? उसने कैश क्राप बोना शुरू किया और जब बाद मे हमको यह मालूम पडा कि देश मे शक्कर होती है, तो शक्कर बाहर भेजी जाती है, मूगफली होती है, तो मूगफली बाहर भेजी जाती है, तिल होता है, तिलहन होती है, सरसो होती है, तो तेल बाहर भेजा जाता है और इतने मे मालूम पडा कि देश मे पहली पचवर्षीय योजना तो सफल नही हुई--क्योकि उन्हे कर्ज के लिये भी कर्जा लेना पड रहा था अपना पैसा चुकाने के लिये, माल भेजने के लिये--इसलिये झूठा प्रचार किया गया और तारीफ यह है कि पहली पचवर्षीय योजना पूरी नही हुई, दूसरी बन गई, दूसरी पूरी नही हुई तीसरी बन गई । यह क्या हो रहा है ?

हमारे देश में गया एक स्थान है, बनारस एक स्थान है । वहां कभी आप जाय आप देखेगे वहां कुछ नाई बैठे रहते है । एक जजमान आये, उसको उन्होने पकड़ा और साबुन लगाया । बोला, आपकी दाढ़ी बड़ी कड़ी है और दूसरे को पकड लाया । दूसरे की आधी हजामत बनाई और कहा भाई जरा ठहरिए और तीसरे को पकड़ लाया । तीसरे के बाद चौथे को पकड़ लाया, यानी पैसा किसी तरह से वसूल हो, अपना भला किसी से हो । जब ऐसा करते करते दस, पन्द्रह आदमी बैठ जाते है, सभी उसकी तरफ देखते रहते है, बेचारे इस लायक नही कि और कही चले जाय--किसी की एक मूछ गायब है, किसी के कुछ गायब है, इसलिये वे उस नाई के पराधीन हो जाते है ।

पहली योजना बनाई गई और वह सफल नही हुई तो दूसरी बना गई । इसी तरह से सरकार योजना बनाती ही चली जा रही है । क्या कारण है कि आप योजना बनाते वक्त इस बात का विचार क्यों नही करते कि हम योजना को सफल भी कर सकेंगे या नही ? आपको अनुपात के अनुसार योजना बनानी चाहिये ताकि वह पूरी हो सके । इसी तरह से तीसरी योजना बनाई गई जबकि दूसरी पूरी नही हो सकी । अब चौथी योजना बनाई जा रही है जबकि तीसरी पूरी नही हुई ।

شری این- ایم- انور (مدراس) : یوجنائیں حضامت بنانے کے لئے ھوتی ھیں -

†[**श्री एम० एन० अनवर** (मद्रास) : योजनाये हजामत बनाने के लिये होती है ।]

श्री गिरिराज किशोर कपूर : यही बात मै कह रहा हू कि योजना इसलिए बनाई गई थी कि देश का भला होगा लेकिन देखने मे यह आया :

जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे,
हमें ही काट खाने को ।

†[ ] Hindi transliteration.

आज देश का क्या हाल हो रहा है, यह सब लोग अच्छी तरह से जानते है और योजनाओं के नाम पर देश को किस तरह से बरबाद किया जा रहा है ? सरकार कहती है कि देश तरक्की कर रहा है । क्या देश की तरक्की के यही माने है ? अगर आप देश की तरक्की के यही माने समझते हैं, तो देशवासी भी आपको अच्छी तरह से समझ गये है ।

श्री गुरुदेव गुप्त (मध्य प्रदेश) : नाग तो आपके गले का हार है वह किसी तरह से आपको डसेगा ।

श्री गिरिराज किशोर कपूर : ठीक बात है । बात यह है कि हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले है । हम सांप को खिलाना भी जानते है और उसको मारना भी जानते है । हमारे कृष्ण कन्हैया ने जब वे पाच साल के थे तो हजार फन वाले नाग के फनों को नाच नाच कर तोड़ कर रख दिया, तो क्या ये एक फण वाले नागों को तोड़ना मुश्किल काम है ? इस देश की जनता के लिए यह काम बहुत आसान है । इस देश की जनता में राष्ट्रभक्ति है, देश प्रेम है और उसको आप चुनौती न दीजिये । आप हम लोगों को कसौटी पर कसने की कोशिश न कीजिये । क्योंकि आज देश संकटकाल से गुजर रहा है । इसलिए हम कहते है कि देश की जो ऊंची सत्ता में बैठे हुए लोग है उन्हें विचार करना चाहिये कि आज देश मे क्या हो रहा है ।

आप देखेगे कि हमारे देश में विधान सभाएं है और लोक सभा है उनका क्या रूप हो रहा है । अभी मैं मध्य प्रदेश की विधान सभा मे बैठा था । मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि जब मैं सामने के बैन्चों को देखता हूं तो मुझे डाकू नजर आते है । इस पर विरोधी दल के लोग बोले कि आपके सामने शीशा होगा । तो वे बोले कि मै शीशे मे क्या देखूगा, आप तो अपनी

[श्री गिरिराज किशोर कपूर]

दाढी का नूर व बिन्दी देखेंगे । तो उन्हें जबाब मिला कि आप बेदाढी मूछ का गुडा तो देखेंगे । जब हम यहा सर्वोच्च पार्लियामेंट को देखते है तो पाते हैं कि हर 15 मिनट के अन्दर घंटी बजती है ।

(Time bell rings)

यहा पर जब हम कोई सवाल करते है तो कुछ मंत्री अच्छी तरह से जबाब नही दे पाते है । श्री चागला और श्रीमती इंदिरा गाधी जैसे कुछ मंत्रीगण है जो जबाब अच्छी तरह से देते है लेकिन कुछ मंत्री ऐसे है जो जबाब ही नहीं दे पाते है और न देने की परवाह ही करते है तथा कह देते है कि हमें इस बारे मे मालूम नही है । आखिर हाउस उनसे हर बात के बारे मे जानकारी हासिल करने की इच्छा रखता है, लेकिन वे कह देते है कि हमें मालूम नही है । मै निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की बात ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नही हो सकती है । यह हमारा हक है कि हम किसी चीज की जानकारी मंत्री जी से हासिल करे, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वे कह देते है कि इस बारे मे जानकारी नही है । कभी कभी तो किसी सवाल को दो मंत्रियो मे विभाजित कर दिया जाता है । अगर मकान के बारे मे कोई बात बतलाई जाती है तो जमीन के बारे मे कह दिया जाता है कि दूसरे मंत्री जी बतलायेंगे । इसी तरह से लोहे या किसी दूसरी चीज के बारे मे मालूम करना होता है तो एक बात एक मंत्री बतलाता है और दूसरी बात दूसरा मंत्री बतलाता है । अखबार चिल्लाते है और विरोधी दल के लोग चिल्लाते है मगर उनकी कोई बात नही सुनी जाती है और न ही जनता को साफ बात बतलाई जाती है ।

सरकार कहती है कि वह सब उद्योग धंधे करेगी मगर जिस काम को वह अपने हाथ मे लेती है उसी मे उसको नुक्सान होता है । एक साधारण आदमी जिसके लिमिटेड साधन हैं जब वह कोई ट्रक खरीदता है तो इस तरह से कार्य करता है कि सरकार के भारी टैक्सों को देकर भी पाच साल के बाद वह नया ट्रक खरीदने के काबिल हो जाता है जबकि उसके पास बहुत कम साधन होते है । लेकिन सरकार जब कोई काम करती है जबकि उसके पास अनलिमिटेड साधन है उसको हर एक काम मे नुक्सान ही होता है ।

मै अब सरकार के पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के कामो के बारे मे आप से कहना चाहता हू । मैंने सरकार से गरम पानी के लिये वाटर बायलर किराये में लिया और मुझे बताया गया कि साढे सात रुपया महीना किराया लगेगा, मैने केवल तीन महीने ही इस्तेमाल किया । जब मेरे पास बिल आया तो उस मे 19.26 रुपये महीने के हिसाब से ४ महीने का कुल 73.05 का बिल बनाकर भेज दिया, जबकि मैने चार महीने से भी कम उसका इस्तेमाल किया था । इसी तरह से फर्नीचर जो कि बहुत ही पुराना है उसका भी २७ रुपये महीने के हिसाब से काटा जाता है ।

श्री महावीर प्रसाद भार्गव (उत्तर प्रदेश) : अगर पसन्द नही है तो वापस कर दीजिए ।

श्री गिरिराज किशोर कपूर : आपने जो राय दी है उसके लिए धन्यवाद और मैं ऐसा कर रहा हूं । मैंने इस बारे में कैलकुलेशन कर लिया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो किराया लिया जा रहा है वह गलत तरीके से लिया जा रहा है और एक तरह से एम० पीज० का लूटा जा रहा है ।

दूसरी बात जो मै कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे देश मे सरकारी विभागो मे तनख्वाह का जो फर्क है वह बहुत ज्यादा है । मेरा निवेदन है कि तनख्वाह मे एक और दस का अन्तर रहना चाहिये अगर ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह 1,000 रुपया है तो कम से कम तनख्वाह 100 रुपया होनी चाहिये । हमारी सरकार कहती है कि देश मे समाजवाद आ रहा है लेकिन जो आदमी 250, 300 या

400 रुपया माहवार पाता है, उसकी बीबी और दो बच्चे हैं तो उसके लिए गुजर करना आजकल बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन आप बड़ी तनख्वाह वालों को तरह तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, भत्ता दे रहे हैं और तरह तरह के आराम दे रहे हैं। लेकिन जो देश की रीढ़ है, जिनके ऊपर आज नाज कर सकते हैं, जो दुश्मन को चैलेन्ज कर सकते हैं, उनके लिए आज सर ढंकने के लिए जगह तक नही है। वे लोग जो झुग्गी या झोपड़ी डालते हैं उनको भी आप तोड़ देते हैं। आज हालत यह है कि गांवों में बेकारी बहुत बढ़ गई है जिससे जनता में असंतोष की लहर फैल रही है। आज सरकार जो योजना बनाती है वह सब शहरों के लिए ही बनाती है जबकि विरोधी दल के लोग यह कहते हैं कि गांवों में योजनाओं को शुरू किया जाना चाहिये ताकि वहां जो बेकारी फैली हुई है वह दूर हो जाय। केवल विरोधी दल के लोग ही नहीं कहते हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी कहते है लेकिन सरकार कोई बात नहीं सुनती है।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस समय देश आपत्तिकाल से गुजर रहा है, इसलिए सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह विरोधी दल के नेताओं तथा योग्य पुरुषों से सलाह ले कर कार्य करे। आज देश में जोश लाने की आवश्यकता है और देश की रक्षा का कार्य किसी एक दल का कार्य नहीं है। इसलिए मैं सदा. से कहना चाहता हूं :

सर फरोशी की तमन्ना हो तो सर पैदा करो,
दुश्मनाने हिन्द के दिल में डर पैदा करो।
फूंक दो, बरबाद कर दो, जो मिटाये देश को,
ऐ शरर वालो जरा दिल मे शरर पैदा करो।

SHRIMATI C. AMMANNA RAJA (Andhra Pradesh): Madam Deputy Chairman, while this Budget is being passed we are faced with an emergency and so we have to take everything into account when we make our remarks. Even the amounts that have been put down under several accounts may not be satisfactory from the point of view of the importance of those subjects when we take them into consideration. But I am afraid even these things will have to be cut down in view of the emergency.

It is a very sad thing that our developmental activities have to be disturbed because of our unfriendly neighbours. Still there is nothing that can be done. When people do not listen to reason we have to rise to the occasion and face the challenge and make all the sacrifices necessary.

One thing that I have to say is this. Mr. Chagla said yesterday that even under ordinary circumstances our Intelligence Department is not functioning properly. More so when there is emergency in the country, when we are faced with emergency at the border, I feel very unhappy that we are faced with difficulties all round. There is infiltration at the borders which we cannot easily expose. There are fifth columnists in the country. There are parties who are more aligned to some other countries than to our own country. So we have to take stock of all those conditions and we have to alert all our people to be completely ready to take up any responsibilities. Particularly at a time like this we have to discourage all strikes. Particularly the students' activities must be channelised into useful activities. They must be told that they are the people who have to save the country and they must take up the responsibility of protecting the country and protecting the freedom that we have won after a lot of sacrifices. This is necessary. I am sorry we did not continue the emergency preparations that we started in 1962; there was a break in it. If we had only continued those prepara-

[Shrimati C. Ammanna Raja.] tions it would have been very useful to us at this present moment. Again we have to start with all earnestness.

Another thing that I wish to say is this. Even though it is 17 years since we attained independence, the dream that we promised to the country has not been completely fulfilled, that is the dream of introducing compulsory primary education. Education is necessary not only to get jobs and make a living, but it is necessary for being civilised and cultured. And when some sections are educated while some others are deprived of this facility it means there is no equality, and when there is no equality there cannot be complete democracy. Therefore, I am glad to say that the Education Minister, particularly the present Education Minister, is very earnest and is trying to do his best. Even some of the Chief Ministers and Education Ministers in the States are trying to do their best. Still we have to wait for a very long time before we can get literacy to all our people. Not all villages even today have got schools, even primary schools. We cannot get them because to provide school buildings, to provide teachers, to provide equipment and all that costs a lot. And I do not know when we will be able to train the requisite number of teachers to take up the work in all the schools of all our villages.

SHRI N. M. ANWAR: But, Madam, on a point of information, Madras State has no village without a school.

SHRIMATI C. AMMANNA RAJA: I am not talking about one State. In general I say there are so many villages even today which have no primary schools.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Not in his State.

SHRIMATI C. AMMANNA RAJA: I do not know about that. If he is sure, I am glad to pay a tribute to that State and to him who has been a D.E.O. for some time. All I say is we have to take it up in all earnestness if we want the people to understand their problems and act accordingly and make the democracy a success. For that it is absolutely necessary that the people must be at least literate and for that we have all to strive.

Madam, some time back some Minister of a State made the proposal that each one of us should teach some people. Those who are educated must feel pity for those who have not this facility and must try and educate their neighbours who are their less fortunate brothers. If all of us feel like that we can advance to some extent at least.

Moreover, Madam, this compulsory education cannot be a success unless we are all unselfish. Today I am sorry to find that many people who are supposed to be social workers and some important people in the country engage minor children in their own houses to look after their children, to do their household work and to work in their factories. Unless this is stopped compulsory education canot be a success. In many societies and in many factories I have seen, particularly in Kashmir where these cottage industries, carpets and handicrafts, are made, small children are engaged. So long as you do not penalise both the parents of the children as also those who engage these minor children in their houses or factories, we cannot make a success. Who is the Minister present?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bhagat is here.

SHRIMATI C. AMMANNA RAJA: I am sorry. So I request the Government to take up this job and take it up earnestly so that anybody who engages minor children either for household work or for work in their

shops or factories is severely penalised.

We are trying to do so much. In many States we have made education free up to the S. S. L. C. particularly for girls. But the girls are prevented from going to school because the parents would like them to earn some money.

SHRI G. M. MIR (Jammu and Kashmir): We have free education in Jammu and Kashmir.

SHRIMATI C. AMMANNA RAJA: In Andhra also it is free for girls. But there are so many handicaps. They have no clothing. Particularly the girls cannot go to schools without proper clothing. And now this system of uniforms has been introduced. Madam, when the daughter of a servant of mine came to me I asked her whether she was going to a school. She said that she had given up because she could not afford a dress. If the Government could give two or three sets of uniform to the children who cannot afford, it will go a long way to educate the children of our country. And as long as it is not there we cannot boast of our democracy functioning properly.

Then, again, there are inequalities in standards from State to State. Some State have got the three-year degree course. Some have got the four-year degree course and some have got public examination at the end of every year. Even with regard to medical degrees there is a lot of difficulty with the result that people who have to be transferred, who have to go from State to State cannot easily get admission for their children.

There is another thing. Even with regard to Hindi, about which we have been hearing a lot, the Centre, I am sorry to say, is very much obsessed only with Madras. They think that South means only Madras or Tamilnad. They can do whatever they like. But in most other States of the South Hindi is compulsory; unless they get a pass mark in Hindi they cannot be promoted to the next class. In Madras it is not so. Even if they get zero, they

3 P.M. are proposed. Even in public examinations, they have Hindi but they do not pass. Unless all these are made uniform, you cannot encourage Hindi or promote the interests of Hindi first of all and secondly, there are inequalities in standards. How can you say that we all must learn Hindi but even if you get zero, you can promote people? This must go.

SHRI JOSEPH MATHEN (Kerala): What is your suggestion regarding Madras?

SHRIMATI C. AMMANNA RAJA: With regard to any State, it must be made compulsory. Even the people of that area admit that they have to learn Hindi but they want some time but make it compulsory. Even though you do not introduce Hindi as the official language, Hindi must be taught and it must be learnt. Some time or other it has got to be the official language.

With regard to the I. and B. Ministry also, it has to be more effective. Where you want to reach the masses with reference to either Hindi or Family Planning or with regard to our activities in the emergency, you have to have at least a community broadcasting set in every village. Our Ministers, when they are asked as to how many villages have not got them, do not tell us the information. They only tell us so many villages have got. How many have not got so far? Actually it is necessary that each one must be in possession of a transistor set because a radio in the house is not of use when you go to work or on camp or other places. But that is not to be because we have high taxation and high duty has to be paid for these. Somehow if we have a factory and if

[Shrimati C. Ammanna Raja.]
we make it very cheap and available to every individual, we can educate our people and reach the masses in all matters about which they are expected to know. We do not even have a powerful transmitter. That is why we cannot go beyond a particular range. It must have been repeated here several times that even about the death of our late Prime Minister Nehru, people had to learn from other countries' stations because we could not reach them. Our transmitters are very weak. Something must be done. There are some things which have to be attended to urgently and this is an urgent matter. Particularly this must have been repeated that even when China attacked us, our jawans did not know what was happening and even the people who took our arms and food supplies dumped them in the occupied area because they did not know that they were occupied. If you want such things to be eliminated, our Information and our Intelligence Department must be made very effective.

About the rail-*cum*-road bridge at Rajamundry, we have given a Calling Attention Notice but so far nothing has come out. It is tried to be treated as a State subject which should not be the case because it is a national highway and this is a very necessary thing. It would cost only Rs. 2 crores and one crore our State Government is prepared to meet. We are only asking for one crore from the Centre as loan and this is a very important thing. There is no bridge on the river Godavari so far and if you want to cross it, it is very difficult and you have been hearing of so many boat tragedies and if you want to avoid them, if you have any value for human life and human effort it has to be granted. I do not know why anybody should be so stubborn about it. Out of thousands of crores that we are spending, cannot one crore be given to a State, a forward State, a State which is doing so much with regard to the supply of food to the country? From Calcutta to Madras it is a national highway and it is diverted for 30 miles for a bridge that is to come up elsewhere. We are only asking for this one crore loan because so many military trucks are also coming there and there is a bottleneck on this railway bridge and if it is made a road-bridge, it will be very useful. People are wanting to strike till death or go on fast unto death for this. We are not troublesome people. We are law-abiding and we are loyal and that is why things are taken for granted. It is not fair, this is not justice, this is not fairplay and I request the Government to see that the people who are loyal and good are not penalised, and are not treated with contempt, are not hurt so badly that they are compelled to resort to activities that are not good.

SHRI R. S. KHANDEKAR (Madhya Pradesh): Madam, we are passing through a very critical stage at this moment. Although there is a lull on the Kutch border, and the hon. Prime Minister is going to make a statement—we do not know whether he is announcing a cease-fire or whether he is announcing more military engagements on the border. Similarly there are alarming reports in to-day's Press that there is heavier concentration on the eastern borders and also in Kashmir—in the so-called Pakistan-occupied Kashmir—evacuation of civilians has been ordered. We do not know what is the plan behind this. We must be prepared for all eventualities and I wish the Government will take serious note of the situation but I find in to-day's papers also that there are feelers for easing the situation. I do not know if it is an Anglo-American trap or at whose instance this feeler is being spread or propagated. I mean that there is a suggestion that this dispute of Kutch should be referred to the International Court of Justice. I would like to give a note of caution that we had committed this mistake when we referred the Kashmir question to the

U.N. and after so many years, probably more than 16 years, the dispute is still hanging there. Similarly, after the Chinese war, we accepted the Colombo Proposals and nothing has been done with regard to those proposals and still there is a stalemate on this issue. The enemy forces are still on our borders and I wish the Government should not commit the same mistake by referring this to the International Court of Justice. We have only recently heard the statement of the Prime Minister that there is no dispute with regard to Kutch. When an issue is referred to any Court of Justice, naturally there is a dispute and so it is referred. In this case there is no such question and if there is a suggestion and if it comes from any of the Big Powers who have helped us or who are helping us, we should reject it outright.

Then to meet this situation of foreign aggression our defence preparations must be adequate and there should not be any miserliness with regard to such matters. I am quite sure that our Army is well prepared, and our Air Force also should be equally well prepared for this. But I am sorry to find that we have been neglecting our Navy in this regard. I had asked a question also about it and the answer was that the priorities given for their improvement or expansion were as follows, first Army, then Air Force and then Navy. That means that the Government is complacent, that they see no danger to our coastline and that therefore they can afford to neglect it. But I would like to submit, looking to the vast coastline of 3,000 miles or more, our Navy is very small, very negligible, compared to the vastness of our coastline.

Recently I had the privilege of visiting some of the naval establishments and I was amazed to find that we had only one warship worth the name for such a long coast, for the coastal protection of this country, and that one ship was Vikrant. It was a very good ship, and looking to the length of our coastline we should have at least three or four such ships. I had a talk with the naval authorities and they were also surprised as to how the Government was so complacent about this matter. They also felt that money should not be the consideration in regard to such matters. And the most surprising factor was that a ship like Vikrant had no berthing facilities in any of the ports in India. It was standing in mid-sea and we were given to understand that on account of its so standing there was a lot of waste, of men, of electricity, of materials, that a lot of people had to be maintained there, because there were no berthing facilities. The officer said that if good berthing facilities could be had for the ship anywhere, at any port, so much energy and so much money could have been saved. I find in the reports also that there was an effort and there is an effort to enlarge the Bombay dockyard, but on account of certain difficulties the work was not proceeding apace, and the difficulty was that originally the work was given to a particular contractor. But he did not fulfil his commitment and therefore his contract was cancelled. And now the naval authorities have taken the work upon themselves and I think the work will be completed very quickly. So I again submit that our navy should not be neglected and more attention than what we are giving now should be given to such matters.

We now and then praise our jawans, and they do really deserve our praise. But I am sorry to find that they do not get any facilities, which they should really get. Only the other day it was a distressing sight to see at Gwalior railway station. The train was already running late and the jawans proceeding from Gwalior had to go by that train to report themselves for duty at the defence stations to which they were posted. But no special arrangement of transport was made for them, and there

[Shri R. S. Khandekar.]

were a number of them. So they had to fight their way at the station platform against other passengers. There were very anxious moments and there was also trouble with their own fellow jawans who were already in the train at that time. So I fail to understand why special transport could not be provided to such jawans who were in numbers at that time. At the time I happened to be at the Gwalior station and the Gwalior unit of the defence forces was being transferred or the men posted to outside places and hence this incident at the Gwalior station. There was actually a fight between the jawans who were on the platform and the other jawans who were in the train. I do not think that this is the moment when the jawans should fight amongst themselves over such matters, and I wish that Government should take serious notice of this and afford full facilities for the transport of our jawans.

Having said this, Madam, I come to an important point which is every now and then discussed in this country.

We have heard a lot about corruption at the highest level. We have had discussions also here. Many allegations were made and are being made against many of the Ministers. There were allegations against Orissa Ministers, against Mysore Ministers, against Bihar Ministers, and so on. But nothing has been done; nothing positive or tangible has been done regarding those allegations. Now I would like to point out one instance of my State also. There is no allegation as such, but it is a matter of high impropriety. Madam, you might have read in the papers that one of the Ministers of the Madhya Pradesh Government, who was the Health Minister, had resigned recently. And why he had to resign? It was for this reason. After he became the Minister, he got some contracts from the Madhya Pradesh Government for his printing press. Then one of the voters made a complaint to the Election Commission and the enquiry proceeded. Now this hon. Minister, at that time, raised all the pleas of a defendant, which are raised in any ordinary suit. He gave a statement on oath that he did not own this press, that he did not have any share in that press, etc. Bill after taking evidence the Election Commission came to a conclusion adverse to him and passed very strong remarks against this Minister. The Election Commission said that his affidavit was most unworthy, was not believable, and that such a statement on the part of a Minister was not proper. Now look at the audacity of the Minister. Even after these strictures the Minister issued a statement saying that under the Constitution he could remain in the Government for six months more but to keep up high standards of morality and integrity, to show the way to others, he was resigning from his office. Then subsequently his resignation was accepted. Now I want to ask: What about the salary he took? What about the allowances he drew from the day the complaint was made from the day he accepted the contract somewhere in January 1964 till the day of his resignation in 1965? During all these fifteen months or sixteen months as a Minister he must have enjoyed all the privileges, he must have drawn salary and allowances as such. What about this amount? Did he not misappropriate this amount? Is it not a sort of dacoity committed on the treasury?

Therefore I demand that at least in future, whenever such instances occur apart from the disqualification incurred as in this case, all the misappropriated money also should be recovered. Of course in this case he has not incurred the disqualification that he cannot stand again for election. But you will be surprised to find that some efforts are now being made to put him again as a candidate to fill the vacancy which has been declared on account of his resignation. This is the standard . . .

SHRI P. K. KUMARAN (Andhra Pradesh): What happened to the contract?

SHRI R. S. KHANDEKAR: Well, he got all the money; he got all the profits; he also got his salary and allowances which he did not deserve and he quietly resigned saying this that he could remain, under the Constitution, as a Minister for six months more. Now this is the highest standard we find in high quarters. We hear many things about morality, honesty, integrity, high standards of conduct and behaviour, and so on but, as in this case, where we expect good standards, we fail and we find the opposite of it.

PANDIT S. S. N. TANKHA (Uttar Pradesh): May I ask the hon. Member, what was the fault of the hon. Minister in this matter? The only thing, so far as I know, was that one of the candidates against him wanted to fight the election against him but his nomination paper was rejected. How is the Minister to be blamed in the matter then?

SHRI R. S. KHANDEKAR: No, no, you are mistaken. This is a different case. Here he accepted a contract from the Government and incurred a disqualification to continue as a Minister. This was after he became a Minister and it seems he knowingly accepted the contract, because he put up defence against the complaint lodged with the Election Commission. Supposing by mistake, not knowing the disqualification likely to be incurred thereby he had accepted the contract, he should have owned the mistake immediately after the matter came to his notice. In that case he would not have given a statement on oath. At least this was not expected of a Minister. We can understand an ordinary man sometimes filing false affidavits in law courts, and when the matter is decided against him, nobody bothers to file a case against him for filing a false affidavit. In the case of this Minister also the affidavit was false and I do not understand why this Minister should not be proceeded against for perjury. He had given a wrong statement on oath and the Election Commission has given a very interesting judgment which has been published in the Official Gazette.

After this I come to a point to which reference has been made by some of the other speakers also and that relates to the reclamation of the ravines which are generally called the Chambal ravines. They cover not only the ravines of river Chambal but they cover also so many other rivers which are there. It is on account of these rivers that there are these ravines. They are very old and there is not a single stone there. If proper effort is made this land can be utilised for agriculture and this will also help in solving the serious problem of the dacoits in the northern part of my State of Madhya Pradesh.

Madam, recently there was a statement by one of the leaders of the S.S.P.—I do not believe that statement is correct—that a parallel government has been established by the dacoits in that area and that they are trying to extort money, that they abduct persons and then demand ransom and those who do not give this money are killed, that there is no civil authority. Even though we do not accept his statement as wholly correct the situation there is very grave and recently there were murders when eleven persons were killed. They were made to stand in a row and killed by point-blank shots. There is much lawlessness in that part of the country, although there is no parallel government. The solution of the food problem is also equally connected with the development of this Chambal Valley and I hope more attention will be given to this problem. Today's paper also gives us some idea that the three States, Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh, have

[Shri R. S. Khandekar.]
been trying to evolve some sort of a plan to reclaim these ravines and to rehabilitate some of the refugees.

Next I come to another problem which is also serious throughout the country and more so in my State, and that is about power. We are constructing so many projects and we expected that after their completion there would be enough power for the development of the industries and agriculture. I do not know about the other States, but I am very sorry to say that in my State though we have had the hydro-electric project completed, and we expected to have enough power this year there is acute power shortage and recently we have had reports that in the cities of Indore, Gwalior and Bhopal the power supply is curtailed and all the industries are partially run. There is going to be a great setback in the industrial production. We are in an emergency now and such power failures are not commendable. I do not know the reason. The Government version is that there was no good monsoon this year and the level of the Chambal Dam fell down and that there was no adequate water to start those generators and so they had to curtail the power supply. But the popular version is that there is something very seriously wrong with the whole construction of the dam and that the water is leaking out and that in spite of the good monsoon or rather the average monsoon that we have had, the water level is going down and down every day. So an expert committee is needed to go into this matter and investigate it. I cannot say why it is, but the fact remains that there is great power failure and industrial production is being hampered very seriously.

Only two days back I had asked a question about food production target in this country and I was given one statement. That statement showed that every year the production in agriculture has been going down and only this year, it is expected that the production in the country will be more than the last two years. Even then it would not be reaching the target of the Third Plan of about 100 million tons. This year it may be 90 or 95 million tons, I do not know. And the Minister also said that as a result of the good harvest the prices of foodgrains would come down and the people would not feel the shortage of foodgrains. But I am very sorry—and Madam, you must also have read about it—there is acute shortage of wheat in Indore. At Indore one of the meetings to be addressed by the Food Minister and Shri Atulya Ghosh could not be held because there was no wheat for 15 days and the people were asking for wheat. They tried to hold that public meeting but it could not be held and ultimately they had to cancel it. One finds there is not enough foodgrains and there is shortage in many parts of the country.

In Maharashtra and Gujarat also foodgrains are not available firstly, and even if they are available, they are of very poor quality. The Government have said that they have fixed some prices for these foodgrains. I have also put a question about this matter. I find that the Government fixes the prices so late that the cultivator has to sell away his wheat at whatever prices he can get. It is after that that the Government announces its prices when there is no more wheat with the cultivator to be sold and all the profit is being collected by the traders who got their wheat from the cultivators earlier. So there is a sort of complacency on the part of the Food Minister, or maybe they rely on the official reports that everything is all right and everybody is happy with regard to foodgrains. But in fact, that is not so.

Next, I come to the question of information and broadcasting. Everybody must be hearing the news given out by All India Radio and other programmes. We find that they are not at all interesting. They are drab programmes. Apart from that—I had

also a question on this subject—there is a sort of partiality in broadcasting certain news items. Also with regard to broadcasting the proceedings of the two Houses of Parliament, I find there is some partiality. One day I was hearing this item on the radio and no mention was made of the proceedings of this House. I asked a question about it and the reply was that importance was being given to news items. I do not know whether the Minister of Parliamentary Affairs attaches no importance to the proceedings of this House on Friday or on non-official days? Why the proceedings on non-official days are not covered by these news items, I do not know.

Similarly, whatever news items are announced, they are not announced properly by the All India Radio and they do not seem to have the least notion about the speakers or their political affiliations. Once I was hearing the news and one Member who did not belong to that Party, his name was announced as belonging to that Party and in that coverage it was simultaneously announced in many of the languages also. I wrote a letter to the Director-General requesting him to correct it and pointing out the utter ignorance on the part of the authorities that they do not know after so much time who are the Members and what are their political affiliations. I do hope the hon. Minister will go into this matter. At least the other agencies that give the news are quite alert and only the A.I.R. is found lacking so many times in such matters.

I would like to take this opportunity of repeat the demand that has been made for a full-fledged radio station at my place, Gwalior. I have been demanding this ever since I came to this House. It is a good thing that some relaying centre has been opened there. That is not enough. Whatever machine has been installed that is of very poor quality. There is good music talent available there in Gwalior and so a full-fledged station should be opened there.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair].

I come to the last but very important point, about the language policy and about education. It is said that the three-language formula has been adopted by all States excepting one or two but that it has not been adhered to. I do not hold any brief for English and I do not say that Hindi should not be the national language but I would say that a policy of going slow should be observed in such matters. Even some of the Hindi-speaking States, including my own, have adopted Hindi as the language of the State and I have no quarrel with it but I wish to point out some of the difficulties. We have created so many all-India Services in this country and we are going to create so many in the future. There are also other matters in which the Centre is interested and where people from the Centre could be sent. Unless Hindi develops sufficiently well or unless all the officers are conversant with Hindi, it would not be possible for them to work in the Hindi-speaking States if Hindi is declared as the language of the State. The ultimate result will be that the choice will be restricted to the four States only so far as the officers of the IAS and the IPS are concerned and these States will be deprived of the talent and the advantage of the other States. Unless Hindi develops sufficiently well and unless all the officers become conversant with Hindi, there should not be compulsion and there should be a little latitude as far as this question is concerned. We must develop Hindi, and there is no doubt about it but no language can ever be imposed overnight. There should be observed the policy of "go slow" with regard to Hindi.

Lastly, I wish to point out one thing. The Report of the Home Ministry has said something about prohibition. I want Government to clearly state the policy with regard to prohibition. On page 56 of the Report, it is said:

[Shri R. S. Khandekar.]

"*It is the intention that* the Report of the Study Team together with the views of the State Governments should be considered at a meeting of the Chief Ministers of States in order to evolve a coordinated programme for effective implementation of prohibition in the dry States and for speedy introduction in the wet areas of partially dry States and the wet States."

The meaning of this is that Government wants to introduce prohibition in all parts of the country, effective introduction in the dry States and gradual introduction in the wet States but I was amazed to find, Mr. Vice-Chairman—and you must also have seen that press report—about the opening of a liquor shop in Poona which is in Maharashtra which is a dry State. One of the sons of a Member of the Legislative Assembly opened a liquor shop and it was inaugurated by one of the Congressmen and the ceremony was attended by the Commissioner of Poona, the Collector of Poona and other high officers of Poona. If you are going to encourage liquor shops in dry States how would you effectively implement your policy of prohibition in this country? I am not against prohibition. I say that there . . .

شری عبدالغنی (پنجاب) : ولائیتی شراب تھی یا دیسی -

†[श्री अब्दुल ग़नी (पंजाब). विलायती शराब थी या देसी]

SHRI R. S. KHANDEKAR: I do not know, I did not attend the function.

SHRI P. K. KUMARAN: Was it a legal liquor shop or illegal liquor shop?

SHRI R. S. KHANDEKAR: Since the Commissioner and the Collector attended I presume that it was a legal one.

†[ ] Hindi transliteration.

SHRI P. K. KUMARAN: That does not prove anything. They are all in the hands of the people, who sell illegally.

SHRI R. S. KHANDEKAR: Whatever it is, when people in authority encourage such functions, what is the sense in saying that prohibition should be enforced effectively? These are some of the points which I wanted to raise on this occasion and as my time is also up, I resume my seat. I thank you very much.

श्री सुरजीत सिंह अटवाल (पंजाब): मिस्टर वाइस चेयरमैन, सर, मैं ऐप्रोप्रिएशन बिल, १९६५ को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं बहुत से दोस्तों की इस बात से इतिफ़ाक नही रखता कि इस देश में कुछ नहीं हुआ और हर तरफ तबाही ही होती रही है । यह गलत बात है । बहुत कुछ हुआ है, मगर यह है कि वह बहुत महंगे भाव पर हुआ है और वह प्रापर प्लानिंग न होने की वजह से हुआ है । मेन जो चीज है, वह यह है कि हम लोगो ने प्रापर प्लानिंग नहीं की, जिस की वजह से बहुत सी गलतियां हम लोगो ने की है। मगर यह नही है कि हम ने देश के लिए कुछ किया नहीं है । हम ने बहुत कुछ किया है, मगर या तो हमने बहुत से ऐसे काम किये हैं जिन की वजह से बहुत सा खर्चा उठाना पड़ा या बहुत से ऐसे खर्चे करने पडे जिन की ज़रूरत नहीं थी । मिसाल के तौर पर हमने नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाया, जिस के ऊपर कोई सौ करोड रूपये के ऊपर हम ने खर्चा इस लिये किया कि थर्ड फाइव ईयर प्लान के आखिर में हमको ११३ मिलियन टन कोयले की ज़रूरत है । मगर इसकी पोज़ीशन यह है कि हमारा तीसरा फाइव ईयर प्लान खत्म होने वाला है और ८० से ८५ मिलियन टन कोयला जो इस वक्त हम रेज़ कर रहे है, उसको

किसी जगह पर कंज्यूम करने के लिये हमारे पास जगह नहीं है । हर साल एक से दो मिलियन टन के करीब कोयला पिटहेड्स के ऊपर बचा रहता है । जो हमने नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन चालू किया, वह इस खयाल से चालू किया कि प्राइवेट सेक्टर जो हैं वह जितने कोयले की हमको जरूरत है, उतना निकाल कर के नही दे सकेगा और बहुत जल्दी में आ कर के हम लोगों ने यह सैकडों करोड़ रुपया उनके ऊपर खर्च कर दिया । मध्य प्रदेश में कोबा माइन्स के ऊपर एन० सी० डी० सी० ने १२ करोड़ रुपये का खर्चा किया और इस खयाल से किया कि वहां पर चार लाख टन कोल वे मथली रेज करेंगे और उसको उठाने के लिये और दूसरी जगह पर ले जाने के लिये २८३ मील रेलवे लाइन साउथ ईस्टर्न रेलव ने बनाई जिस के ऊपर ५० से ६० करोड़ रुपये के दर्मियान खर्च हुआ । मगर आज उस जगह की पोजीशन यह है कि वहा हम ८० हजार टन कोयला निकालते है और वह ८० हजार टन कोयला इस लायक नही है कि उसकी हम मार्केट में विक्री कर सके । इस की वजह से यह जितना रुपया हमने रेलवे लाइन बनाने पर खर्च किया और अभी तक वहां जो कुछ हुआ, वह मेरे खयाल से वेस्ट हुआ है । अगर उसकी प्रापर प्लानिग होती और उसको प्रापर चैकिंग की जाती और जल्दी मे आकर हम इस कदम को न उठाते तो यह देश का इतना रुपया किसी और काम मे लग सकता था । एन० सी० डी० सी० के कोल के काम मे आने की वजह से बहुत सी चीजें हुई, क्योंकि इस ने कोल रेज़ करने की कास्ट इतनी बढ़ा दी थी कि प्राइवेट सेक्टर भी हल्ला मचाता था कि कोल की प्राइस बढ़नी चाहिए और एन० सी० डी० सी० की कास्ट को देख कर के प्राइवेट सेक्टर से कोल की कीमत भी दो तीन दफ़ा बढानी पड़ी । हम प्राइवेट सेक्टर को चेक करने लिए गए, मगर गल्ती की वजह से और प्रापरली काम न करने की वजह से प्राइवेट सेक्टर को एडवाटेज ही मिला । तो मेरे ख़्याल में आगे के लिए हम को ऐसा कदम नही उठाना चाहिए, जिस से कि बजाय इस के कि हम प्राइवेट सेक्टर की राइजिग कास्ट की डिमांड को रोके, हम पबलिक सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स है उनकी कास्ट इतनी बढ़ाते जायें कि उसको देख कर के खामख्वाह अपने आप को बचाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के प्रोडक्शन की कास्ट को, उनकी सेलिग प्राइस को, बढाते जाना पडे ।

شری عبدالغنی : اور یہ سچ ہو جائے کہ کوئلہ کی دلالی میں منہ کالا

†[श्री अब्दुल गनी : और यह सच हो जाये कि कोयले की दलाली में मुंह काला ।]

श्री सुरजीत सिंह अटवाल : मुंह काला तो जहां जरूरत पड़े उसी वक्त हो सकता है ।

अब, तीन स्टील प्लांट में हमने बहुत सा रुपया खर्च किया । जब प्राइवेट सेक्टर में स्टील प्लांट्स चलते थे तब लोहे के भाव 600 या 500 रु० टन थे । और अब 750 या 800 रु० टन हो गए है । तो हम ने प्राइवेट सेक्टर को चैक नही किया, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को इस हालत में लाकर के खड़ा कर दिया कि वे हमेशा हमारे सिर पर डंडा ले कर खड़े रहें । तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पबलिक सेक्टर में जो चीज हम करना चाहते है उसके लिए जब तक हमारे पास पूरे साधन न हों , जब तक हम उनको एकानामीकली, कम्पीटीशन मै आ कर, चला न सकें, तब तक जल्दी में आकर उन के ऊपर इस तरह से रुपया वेस्ट न किया

†[ ] Hindi transliteration.

[श्री सुरजीत सिंह अटवाल]

जाये जो कि हम हर एक तरीके से लोगों की कमाई से टैक्स लेकर या जिस तरीके से भी हो, इकट्ठा करते हैं।

दूसरी बात यह है कि हमारे देश में सब से ज्यादा जिस चीज की शार्टेज़ पड़ती है, वह खुराक की है, । खुराक के बारे में बहुत सी स्कीमें बनती हैं मगर आगे चल कर के कोई एक्शन में नहीं लाई जातीं । पीछे हमारे देश में खाने की चीजों की बहुत कमी आई और बहुत से फैसले किए गए और इन फैसलों को अगर लागू किया जाये तो देश में खाने की चीजों की कमी नहीं रहेगी, मगर मुझको अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक उन फैसलों को हम लोगों ने लागू नहीं किया । अगर हमें अमेरिका के ऊपर ही हमेशा डिपेंड रहना है कि वह हमें खाने को देता रहे, तो ठीक है । हमको कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर अमेरिका से मंगा कर खाते रहने से हम को बचना है तो हमको जो फैसला करते हैं उन पर रीयल मानों में एक्शन लेना होगा । अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो आटोमैटिकली खाने पीने की जितनी चीजें जरूरी हैं और जितनी मिकदार में हमको ज़रूरत है वह हमें कभी भी मुहैया नहीं होंगी । पिछले वर्ष में सरकार के कुछ फैसले अच्छे हुये लेकिन इस ख्याल से बचा जाये कि बस हमारी प्राबलम साल्व हो गई है । यह एक बहुत बड़ा धोखा है और इसके जरिये हमें बहुत सी मुश्किलात आगे सहनी पड़ेगी । हम लोगों को एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए सही मानो में उन लोगों की मदद करनी होगी जो कि खुराक पैदा करते हैं। और उन के पास एकानामिक होल्डिंग्स हैं या नहीं हैं, यह देखना होगा, उनको मैकेनिकल तरीके और ट्रैक्टर्स वगैरह सप्लाई करने होंगे और वह जितनी भी जल्दी सप्लाई किया जा सके उतना ही हमारे लिए अच्छा है । इसलिए मैं मिनिस्टर फार फूड एंड एग्रीकल्चर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वह सही मानों में खुराक के मसले को हल करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द उन फैसलों को, जो उन्होंने पहले किए थे, लागू करें।

दूसरे, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कुछ एक्शंस लिए हैं कि काला धन किसी तरह से बाहर आ सके और उसके लिए उन्होंने बहुत सी सहूलियतें लोगों को दीं जिस से कि वह उस रुपये को बाहर ला सकें, मगर मेरे ख़याल में जितना रुपया बाहर आना चाहिए था वह नहीं आया और इसकी वजह मेरे ख्याल में यह है कि जो छोटे बिजनेसमैन अपना काम करना चाहते हैं, उनको बैंक से या फाइनेन्सियल कार्पोरेशंस के जरिए से इनवेस्ट-मेंट की जितनी सहूलियत होनी चाहिए उतनी नही है और इस वजह से उनको उन लोगों के पास मदद लेने के लिए जाना पड़ता है जिन के पास यह रुपया है, जो कि नम्बर दो का कहा जाता है, यह रुपया जिनके पास पड़ा हुआ है उन से उस रुपये को लेकर के उनको काम चलाना पड़ता है । तो जब इस तरीके से वह रुपया मार्केट में चालू रहेगा तब कोई भी आदमी यह कोशिश नहीं करेगा कि ४० और ६० की बेसिस पर गवर्नमेंट के सामने अपना रुपया डिक्लेयर कर दें । तो मैं फाइनेन्स मिनि-स्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह बैंक्स और दूसरी जो फाइनेंसियल कार्पोरेशंस हैं उनको कहें कि वे मिडिल क्लास बिजनेस-मैन को रुपया अच्छी सहूलियतों पर दें जिस से कि बजाय इस के कि वे लोग अंडरग्राउंड रुपये को लेकर अपने बिजनेस में लगायें, बैंक और फाइनेन्सियल कार्पो-रेशंस से रुपया ले कर अपना काम चला सकें । जब वह रुपया जो कि इस वक्त छिपा हुआ है किसी के कारोबार में नही लगेगा तो आटोमैटिकली वह बाहर आ जायगा और बाहर जेनविन बिजनेस में लगना शुरू हो जायेगा । जिसके जरिए

से गवर्नमेंट को टैक्सेज़ और रेवेन्यू ज्यादा मिलेगी ।

दूसरी फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी यह रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से वह यह रूल लागू करते हैं कि जो आदमी इंकमटैक्स का पेमैंट नहीं करता या रेवेन्यू नहीं देता उसको हर तरह की सजा दी जा सकती है । उसी तरीके से कुछ ऐसा रूल भी लगाएं कि पबलिक सेक्टर में या प्लानिंग में जो करोड़ों रुपया वेस्ट करते हैं उन के ऊपर भी कोई एक्शन लिया जा सके । जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हमने देश में बहुत कुछ किया है, मगर किया है बहुत महंगे भाव पर और किया है बहुत आहिस्ते, आहिस्ते ।

इसी तरीके से हम आज एक मुश्किल के सामने एक मुसीबत में आ पड़े हैं । हमने अपनी फौज को शांति से बढ़ाना शुरू किया इस शांति से, इस आसानी से उसको बढ़ाते गये कि चाइना ने जिस वक्त हमारे ऊपर अटक किया उस वक्त हमने दिल को समझा लिया, दिल को तसल्ली दे दी, लोगों को तसल्ली दे दी कि वह एक बहुत बड़ी ताकत है, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं । आज पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हमारी जमीन का हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया । क्या इस वक्त भी हम यह कहेंगे कि यह भी एक बहुत बड़ा देश है, क्या इस वक्त भी हम अमेरिका से हथियार मांगने के लिये जायेंगे? मेरा खयाल है कि अगर हमको अमेरिका से हथियार ले कर, अमेरिका से हथियार मांग कर पाकिस्तान से लड़ना है तो उससे हमें मर जाना बेहतर है । तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे डिफेंस मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब इतना रुपया हम डिफेंस सर्विसेज के ऊपर खर्च करते हैं तो क्यों न उनका जल्द से जल्द समय में ऐसा लायक बना दें कि कोई देश हमारी तरफ बुरी निगाह से न देख सके । मगर आज हाल यह हो चुका है, पहले चाइना उठाता है, फिर पाकिस्तान उठता है और कल हो सकता है सीलोन वाले भी कहें कि समुन्दर पार हमारा भी हिस्सा है । तो मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे जल्द से जल्द अपनी फौज को हर तरीके से मजबूत करने का बंदोबस्त करें; नहीं तो जिस तरह से आज देश की हाल है, पबलिक का मारल हमेशा गिरता चला जायेगा ।

कुमारी मणिबेन वल्लभभाई पटेल (गुजरात) : आज शाम को कच्छ के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ निवेदन करने वाले हैं, ऐसा मैं ने सुना है । आशा करती हूं कि इस हाउस में भी करेंगे ।

कच्छ के बारे में मुझे यह कहना है कि पिछले सेशन में भी मैं ने आरम्भ में कहा था कि जिस तरह से चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया उसके बाद हम जगे । हमारी तैयारी नही थी, हमको धोका दिया गया, ऐसा हमने कहा । अब इसी तरह से कच्छ में न हो, इसके बारे में आपको सावधान रहना चाहिये और देखना चाहिए । मुझे दुःख है कि मेरे कथन पर ध्यान नहीं दिया गया और आखिर यही हालत हुई कि एस०आर०पी० और सी०आर० पी० को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा और बार बार गुजरात सरकार ने दिल्ली को लिखा, एक बार तो खुद आ कर वहां के कर्मचारियों ने बताया । तब भी ध्यान नहीं दिया और काफी दिनों के बाद हमारी फौज वहां भेजी गई और भेजने के बाद भी कई दिनों तक फौज पीछे और आगे एस. आर. पी. और सी. आर. पी रही, यह ढंग रहा । वहां मैं और काम के लिये पिछले महीने की १७ तारीख को तीन दिन के लिये गई थी । मैं ने देखा, वहां के लोग देहात में भी काफी स्वस्थ हैं, उनमें कोई घबराहट नहीं है , कोई ऐसी हवाई बातें चिल्लाते नहीं थे । उन्हें हमारी लश्कर में पूरा विश्वास था और वे चाहते थे कि जो कुछ मदद कर सकें, करें । हर तरह

[कुमारी मणिबेन वल्लभभाई पटेल]

मदद करने के लिये वे तैयार है। परन्तु इतने सालों से गुजरात सरकार कहती रही, बम्बई सरकार थी, तब उन्होंने भी कहा। पर दु:ख की बात है, इधर कुछ उसके बारे में लक्ष्य नही दिया और जो खास छ: सड़कें थीं जो हमारी सरहद के कारण जरूरी थी, उसमे से एक भी नही बनाई और एक सड़क की, जिसकी मन्जूरी दी है, उसकी भी अभी जवानी बात है। पिछले हफ्ते तक न पैसे दिये गये थे और न लिखित हुकम किया गया था और किस तरह से बिना लिखे हुए कोई चीज कैसे कोई कर सकता है?

एक आई० जी० पी० के बारे में यहां काफी बातें चल रही है। मुझे इसमें बहुत दु:ख होता है क्योकि असम में कुछ भी हुआ हो, असम के अन्दर जो पाकिस्तानी मुसलिम्स का इन्फिलट्रेशन हुआ है उसके पहले इतिहास से मै वाकिफ हूं और उसके कई कारण है। आखिर मे, जो कर्मचारी है वह तो ऊपर के मिनिस्टर्स, और जैसी गवर्नमेंट की पालिसी है या जैसी गवर्नमेंट है, उसी तरह से वह काम करते है। मेरा अनुभव है कि जो आई०सी० एस० आफिसर्स हैं, जितनी वफादारी से और जोश से ब्रिटिश सरकार की नौकरी करते थे और उनके हुक्म का पालन करते थे, वही लोग आज हमारी सरकार की भी उसी तरह से सेवा कर रहे है। तो मेरा यह कहना है कि आज गुजरात के आई० जी० पी० के बारे मे जो इधर बातें चल रही है वे मेरी राय मे गलत है और ऐसे मौके पर ऐसी बात कर के किसी कर्मचारी को निरूत्साहित करना और उसको दु:ख लगाना गलत है। मै यह कहना चाहती हू कि जब वे भेजे गये तब लोगो के मन मे भरोसा था, विश्वास था, ऐसा कहा था। सब जानते थे कि असम से आ रहे है और असम की जो स्थिति है वह भी जानते थे। परन्तु मुझे कहना चाहिये कि हमको अनुभव यह हुआ है कि आज उनके बारे मे हम कोई शिकायत नही कर सकते, न सरकार, न लोग। सब को पूरा भरोसा है कि वे अच्छी तरह से वफादारी से काम कर रहे है और इतना ही नहीं बल्कि कच्छ के बारे में जो परिस्थिति हुई उसके बारे में उन्होंने पहले ही सावधान किया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होने कहा कि इतने स्टेप्स नहीं लिये जायेंगे, इतना इतना नहीं किया जायगा तो हमको जोखिम है और आज दिल्ली की सरकार कबूल करती है कि उन्होने जो कहा वह बिल्कुल सही था। इसलिये मैं इस सदन के द्वारा यह बात साफ करना चाहती हूं और मुझे दु:ख है कि हमारे गृह-मंत्री से जब सवाल लोक सभा मे उठाया गया तो उस वक्त तुरन्त जवाब नही दिया गया। रवैया तो यह है कि जो व्यक्ति या जो कर्मचारी अपना बचाव नही कर सकता, जो अपना पौइन्ट आफ व्हयू नहीं रख सकता उसका सदन मे जिक्र नही आना चाहिये। परतु मैं देखती हूं, यह जो रवैया था वह बिल्कुल चला गया है, यह अच्छा नही है, इसका अमल न इस हाउस मे होता है न उस हाउस मे होता है और उसका आग्रह न चेयर रखता है न मिनिस्टर रखता है। यह बिल्कुल अच्छा नहीं है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे साम्यवादियों को कोई भी मौका मिले तो एक बिड़ला के बारे मे न मालूम क्या आकेजन है, कुछ भी हो, उनको गाली देने का यहा मौका लेते हैं और दु:ख की बात है उनको रोका नहीं जाता। आप जेनरल पालिसीज पर कुछ भी कहें, परन्तु एक व्यक्ति का नाम ले कर, जो खुद आकर अपना बचाव नही कर सकता, उसके बारे मे इस तरह से हर मौके पर बात करना चाहते है, यह बिल्कुल गलत चीज है। हमारे गृह-मंत्री कलकत्ता गए और उनके साथ थे और किसी अखबार वाले ने उनका चित्र छापा तो कोई उन्होने तो नही कहा था कि मेरा फोटो ले लो, मेरा फोटो छापो। वह फोटो ले कर कहते है गृह-मंत्री उनके साथ क्यों गए?

4 P. M.

आखिर यह जो सरकार है वह सारे देश की सरकार है। हम उद्योगपतियों को देश से अलग नहीं मानते। वे देश का विकास करते हैं और हम उन्हें साथ लेना चाहते है। सरकार उद्योगपतियों से सहकार लेना चाहती है, अगर हमारे मंत्री जी उद्योगपति जी के घर गये या वे उनके पास आये, मंत्री जी ने उनको अपने साथ बातचीत करने के लिए बुलाया तो क्या हो गया? कोई बुरी बात तो नहीं क और न वे उद्योगपति बुरे ही आदमी है। जो उद्योगपति बुरे हों, हमे उन्हें जरूर शिक्षा देनी चाहिये। लेकिन किसी सदस्य का इस तरह की बातें कहने की लिबर्टी देना मुझे ठीक नहीं लगता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे यहां अब फारेन फर्म्स के साथ एडवर्टाइजमेट के मामले मे कालोबरेशन हो रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि वह इस तरह की बात क्यों करने दे रही है? क्या हमारे लोगों में इस तरह की शक्ति नही है कि वह इस तरह के एडवर्टाइजमेंट का काम कर सकें? अगर हम यहा के लोगों की शक्ति का विकास चाहते है, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको इम्प्लायमेट देना चाहते है, तो सरकार को यह काम यहां के लोगों के जरिये कराने देना नही चाहिये था। अगर सरकार छोटे छोटे आदमियों को आगे बढ़ाना चाहती है, यहां के फर्म्स को आगे बढाना चाहती है, तो यह काम उनको दिया जाना चाहिये। इसलिये मै निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिये।

एक बात मेरी और समझ में नही आती है और मैं दो सालों से इस बारे में कहती आ रही हूं। मैंने यह बात कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब से कही, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि जब हमारा रेलवे विभाग अपना टाइम टेबुल प्रादेशिक भाषा में छापता है और उसमें जो आंकड़े होते हैं वे भी प्रादेशिक भाषा में छापे जाते हैं तो टेलीफून डायरेक्टरी के आंकड़े क्यों नहीं छापे जाते? जब मैं राज्य सभा की सदस्य नहीं थी तो मुझे जवाब दिया गया कि हमारे विधान मे लिखा है कि गुजराती डायरेक्टरी में डिजिट गुजराती भाषा में नहीं छापे जा सकते हैं; बल्कि अंग्रेज़ी भाषा में छापे जाने चाहिये। जब मैंने पूछा कि विधान में ऐसी कौन सी धारा है जिसमें यह बात लिखी हुई है? मैंने यह बात दो तीन बार पूछी मगर कोई जवाब नहीं दिया गया। जब मैं राज्य सभा की सदस्य बनी तब जवाब दिया गया और जब कनसलटेटिव कमेटी की मीटिंग होने को आई तब जवाब दिया गया कि विधान मे तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सुविधा के लिए हमने अंग्रेजी डिजिट छापे है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि इस बारे में उसे ध्यान देना चाहिये कि जिस भाषा में टेलीफोन डायरेक्टरी छपती है उसी भाषा में उसके डिजिट में छापे जाने चाहिये। अगर रेलवे विभाग यह कार्य कर सकता है तो जनता की सुविधा के लिए यह कार्य किया जाना चाहिये। जहा तक डायल के डिजिट का सम्बन्ध है उसमे अंग्रेज़ी के डिजिट रहने देना चाहते है, तो मुझे इस समय कोई एतराज नही है। लेकिन जहां तक टेलीफोन डायरेक्टरी मे डिजिट छापने का सवाल है, उसको अवश्य प्रादेशिक भाषा मे ही छापना चाहिये। अगर हमारे दिलों में राष्ट्रीय भावना है, तो मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जिस भाषा मे डायरेक्टरी छपती है उसी भाषा मे डिजिट भी छापे जाने चाहिये।

हमारे विधान मे नशाबन्दी के बारे में लिखा है, लेकिन अजीब बात है कि

[कुमारी मणिबेन वल्लभभाई पटेल]

जब हम आगे बढना चाहते है तब हमारे कदम पीछे की ओर जाने लगते है। आज किसी ने एक सवाल पूछा कि कोई एक स्टेट शराब का कारखाना लगाने जा रही है या लगाना चाहती है, तो कहा गया कि उसके बारे मे दिल्ली सरकार को देखना चाहिये। लेकिन मै कहना चाहती हू कि अगर इस तरह की कोई बात है तो केन्द्र को उसको रोकना चाहिये। आज आन्ध्र मे काफी अंगूर हो रहे है और मैंने सुना है कि बड़े बडे सम्पत्तिवान् वहां पर जमीन खरीद रहे है। ये सम्पत्तिवान् इसलिये वहा पर जमीन खरीद रहे है क्योकि ये लोग समझते है कि कभी न कभी हमारे यहां से नशाबन्दी चली जायेगी और फिर हम वहा पर शराब का कारखाना शुरू कर देंगे। मै यह बात मानती हूं कि चाहे सारे देश को झोपडी मे रहना पड़े लेकिन हमारे यहां जो नशाबन्दी का काम है उसको रोका नही जाना चाहिये। मैं यह बात मानती हू कि एक कार्यक्रम बना कर इस कार्य को हमे स्टेप बाई स्टेप करना चाहिये जिससे कि यह सारे देश मे कामयाब हो सके। मै यह कहना चाहती हू कि इस सम्बन्ध मे हमारी सरकार की जो नीति है वह बहुत ही ढीली नीति है। यह दुःख की बात है कि जब इस चीज का प्रारम्भ हुआ था तब राष्ट्रपति भवन मे शराब नही दी जाती थी। मतलब यह है, सरकार की ओर से शराब के लिए बिल्कुल भी पैसा नही खर्चा जाता था, लेकिन आज मैने सुना है कि हमारे मिनिस्टर भी पार्टियो मे शराब देने लगे है। सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि टूरेस्ट ट्रैफिक को बढाने के लिए और फारेन एक्सचेंज कमाने के लिए हम अपनी नीति मे ढील कर रहे है। सरकार जो होटल चला रही है उसमे भी काफी शराब दी जाती है। इसलिये मै निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार को इस बारे मे कुछ न कुछ सोचना चाहिये और इस चीज को रोकना चाहिये।

इसके बाद मुझे अन्न की समस्या के बारे मे कहना है। मेरा कहना है कि जब तक आप यह जोन्स का सिस्टम खत्म नही करेंगे और कन्ट्रोल को खत्म नही करेंगे तब तक यह समस्या इस हल होने वाली नही है।

इसके बाद मै यह कहना चाहती हूं कि काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ ये दोनो ही नेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सरकार ने माने है। विद्यापीठो को सरकार की ओर से पूरा खर्चा मिलता था, लेकिन गुजरात विद्यापीठ को यूनीवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन के सुपुर्द कर दिया गया है। जब से उसे इसके सुपुर्द किया गया तब से उसको सरकार की ओर से कोई ग्रान्ट नही दी जाती है और कमीशन की ओर से तो पूरी सहायता मिलती नही है। विद्यापीठ ने कई कमिटमेट किये हुए है, कई मकान बनाने आरम्भ किये हुए है लेकिन न तो सरकार ही पैसा देती है और न ही कमीशन पैसा देता है। इस तरह से काम कैसे होगा? आगरा मे सरकार की ओर से जो हिन्दी का काम हो रहा है उसमे ७०, ९०, ११० रुपया स्टाइपन्ड दिया जाता है लेकिन इस विद्यापीठ को ४० रुपया ही स्टाइपण्ड दिया जाता है। यह जो भेदभाव है वह नही होना चाहिये।

अब मै एक बात प्रोजेक्ट के बारे मे कहना चाहती हू। मै कई सालो से यह बात कहती आ रही हू, लेकिन कोई ध्यान नही दिया जाता है। इस काम के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, मगर वह भी काम नही करती है। लेकिन मै यह कहना चाहती हू कि जो प्रोजेक्ट सेन्टर के हाथ मे है उसमे प्रान्त इस तरह की कोई रुकावट करे, यह कोई कच्छी बात नही है। गुजरात के लोगों के मन मे इस बारे में

बहुत दुःख है और वे चाहते हैं कि नर्बदा का प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा किया जाये, ताकि वहां अन्न की समस्या हल हो सके।

अंतिम बात मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे प्रान्त में गैस मिल गई है लेकिन सरकार जिस दाम में आसाम को दे रही है उस दाम में हमको नहीं देना चाहती है। हमारे प्रान्त में कोयला भी बाहर से आता है जिसके लिए काफी फ्रेट देना पड़ता है। इसलिये मैं कहना चाहती हूं, गुजरात जब कि एक डैफिसेट स्टेट है और उसके साथ दूसरी तरह का ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है; स्टेपमंदरली ट्रीटमेंट आसाम के मुकाबले में क्यों किया जा रहा है? इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये यही मेरा आपसे कहना है।

श्री जगत नारायण (पंजाब) : वाइस चेयरमैन महोदय, परसों जब इस सदन में हमारे प्रधान मंत्री पाकिस्तान के ऐग्रेशन के सम्बन्ध में ब्यान दे रहे थे, तो उसका तालियों से स्वागत किया गया था और दोनों तरफ से किया गया था, कांग्रेस की तरफ से भी और अपोज़ीशन के कुछ मेम्बरों की तरफ से भी। मैं भी कुछ उस स्वागत में शामिल था, मगर मैं कुछ दुःख और शर्म के साथ शामिल था कि पाकिस्तान और चीन के नेता क्या समझते होंगे कि जब कभी इन पर आक्रमण होता है, तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज़ बैठ कर के एक रेज़ोल्युशन पास कर देते है, कागज़ी रेज़ोल्युशन पास कर के चुप हो जाते हैं और अपना इलाका दुश्मन के हवाले कर देते हैं। पिछली दफा १४ नवम्बर, १९६२, को जो लोक सभा में रेज़ोल्युशन पास हुआ था, वह मैं इस हाउस की तवज्जह के लिये पेश करना चाहता हूं :

"This House notes with deep regret that, in spite of the uniform gestures of goodwill and friendship by India towards the People's Government of China on the basis of recognition of each other's independence, non-aggression and non-interference, and peaceful co-existence, China has betrayed this goodwill and friendship and the principles of Panchsheel which had been agreed to between the two countries and has committed aggression and initiated a massive invasion of India by her armed forces.".

आगे सुनने वाला है :

"This House places on record its high appreciation of the valiant struggle of men and officers of our armed forces while defending our frontiers and pays its respectful homage to the martyrs who have laid down their lives in defending the honour and integrity of our motherland.

"This House also records its profound appreciation of the wonderful and spontaneous response of the people of India to the emergency and the crisis that has resulted from China's invasion of India.

"It notes with deep gratitude this mighty upsurge amongst all sections of our people for harnessing all our resources towards the organsation of an all-out effort to meet this grave national emergency. The flame of liberty and sacrifice has been kindled anew and a fresh dedication has taken place to the cause of India's freedom and integrity.

"This House gratefully acknowledges the sympathy and the moral and material support received from a large number of friendly countries in this grim hour of our struggle against aggression and invasion."

लास्ट फिक़रा सुनने वाला है :

"With hope and faith, this House affirms the firm resolve of the Indian people to drive out the aggressor from the sacred soil of India, however, long and hard the struggle may be."

[श्री जगत नारायण]

वजाय चीन का ऐग्रेशन खत्म करने के और अपना इलाका वापस लेने के, ढाई साल के बाद अब हमने पाकिस्तान को इजाज़त दे दी कि वह हमारे कुछ इलाके पर कब्ज़ा कर ले और उसके बाद दोनों सदनों ने बैठ कर के फिर एक रेज़ोल्युशन पास कर दिया । वाइस चेयरमैन महोदय, बताइये कि इन रेज़ोल्युशन के पास करने का क्या फायदा है? चीन और पाकिस्तान के नेता बैठे हुए यह समझते होंगे कि इनके रेज़ोल्युशन बेमानी चीजें हैं; क्योंकि इन्होंने पहला रेज़ोल्युशन पास किया 14 नवम्बर, 1962, को और उस पर इन्होंने अभी तक कोई अमल नहीं किया । तो मैं बड़े अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि आज हमारा सिर शर्म से झुक जाता है कि पहले ऐग्रेशन को हमने खत्म नहीं किया और अब पाकिस्तान ने दूसरा ऐग्रेशन कर दिया और इसके सम्बन्ध में भी हम सिर्फ कागज़ी कार्रवाई कर रहे हैं । पता नहीं आज प्राइम मिनिस्टर साहब 6 बजे क्या बयान देंगे सीज़ फायर के मुताल्लिक । उसके मुताल्लिक तो मैं कुछ कह नहीं सकता । मैं समझता हूं कि अगर सीज़ फायर हो भी जाये, तब भी जो हमने अहद लिया था 14 नवम्बर, 1962 को और जो हमने परसों लिया है, उसको सामने रखते हुये और आज जो हालात हैं और जिस संकट में से हम गुज़र रहे हैं, उसको देखते हुये हमको अपने इरादे की तकमील के लिये पूरा कदम उठाना चाहिये ।

वाइस चेयरमैन महोदय, यहां पर अपोज़ीशन की तरफ से कहा गया, हमारे वाजपेयी जी ने आप को एक सलाह दी कि इस नाजुक मौके पर, इस संकट के मौके पर आप को अपोज़ीशन को अपने कांफिडेंस में लेना चाहिये, और हमारे मौलवी अब्दुल ग़नी साहब ने अपनी तक़रीर में कहा कि आप को नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिये । मै बड़े अदब के साथ शास्त्री जी की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त जो देश में संकट है, वह कोई मामूली संकट नहीं है । सीज़ फायर अगर आज हो भी जाये, तब भी यह संकट दूर होने वाला नहीं है । आप कहेंगे कि कैसे ? मैं बड़े अदम के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह संकट इस किस्म का है कि यह संकट बाहर का भी है और यह संकट इंटर्नल भी है । इंटर्नल संकट कैसे है ? आज हमारे कांग्रेसी भाई इसको तस्लीम करें या न करें, आज हर सूबा के कांग्रेसी कांग्रेसियों से लड़ रहे हैं । हमारे रामकृष्ण साहब ने हमारे सूबा में एक तरफ इमर्जेंसी डिक्लेयर कर दी है और अमृतसर में जो मज़दूर हैं, उन पर उन्होंने इमर्जेंसी लागू कर दी है, मगर उसी के साथ पंजाब प्रदेश के जो कांग्रेसी हैं, वे वहां पर कांग्रेसियों को कांग्रेस से निकाल रहे हैं कि उन्होंने यह काम किया है, वह काम किया है । आज हर सूबे में कांग्रेसी कांग्रेसियों से लड़ रहे हैं और उधर हालत यह है कि चीन और पाकिस्तान हमारा इलाका लेते चले जा रहे हैं । हर सूबे में हमारे कांग्रेसी नेता लड़ रहे हैं और इस तरह वे देश पर ऐग्रेशन का, देश पर हमले का, मौका मुहैया कर रहे है ।

मैं बड़े अदब के साथ-आप की खिदमत में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि अपोज़ीशन बैंचेज पर जो लोग बैठे हैं, उनके बारे में यह मत समझिये कि वे आप के दुश्मन हैं या देश के दुश्मन हैं । वे उतने ही देशभक्त हैं, जितने आप देशभक्त हैं जो कि सरकारी बैंचों पर बैठे हुये हैं बल्कि आप से ज्यादा देशभक्त हैं । आज हालत यह है कि इस वक्त हमारे साथ कोई देश नहीं है । 14 नवम्बर, 1962, के प्रस्ताव में आपने उन फ्रेंडली नेशंस का शुक्रिया अदा किया था, जिन्होंने हमारी मदद की थी, मगर आज कोई ऐसी फ्रेंडली नेशन नहीं है, जो पाकिस्तान के मामले में आपकी मदद को आये । इस वक्त न तो कोई कंट्री आप की मदद को आने वाला है और न आपका कोई पड़ोसी आपकी मदद को आने वाला है । इसलिये याद रखिये कि इस वक्त अगर कोई आपकी मदद कर सकता है तो वह आपका

देशवासी ही कर सकता है और यह लोग कर सकते है जो अपोजीशन में बैठे हुए हैं। हम हर रोज प्रधान मंत्री का बयान सुनते रहते है कि कंजरकोट खाली कराये वगैर हम कोई सुलह नही करेंगे और आज पता नही कि वे किस तरह की सुलह करते हैं। मगर एक बात मै कहना चाहता हूं कि दोनों हाउसेज में जिस ढंग की तकरीरे होती है, उससे देश का भला नही होता है। आज जरूरत यह है कि हमारे प्रधान "ऊंचे उठें और अगर वे नेशनल गवर्नमेंट बना सकें, तो उनको बनाना चाहिये।"

जब देश आजाद हुआ था और जब बटवारा हुआ था, तो महात्मा गांधी ने जो पहली कैबिनेट बनवाई थी यहां हिन्दुस्तान मे, उसी मे श्यामा प्रसाद मुकर्जी भी थे, उसमे भाभा साहब भी थे, उसमे जान मथाई साहब भी थे, उसमे अकाली पार्टी के सरदार बलदेव सिंह भी थे और इस तरह उन्होने उसको एक नेशनल गवर्नमेंट की शक्ल दी थी, ताकि दुनिया को बता सकें कि हम को आजादी मिली है, तो हम आजादी को, अपने हाथ में बरक़रार रख सकते है और देश को आगे ले जा सकते है। आज देश पर बड़ा भारी संकट है। इधर तो अपने अन्दर संकट हैं, आपस के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और उधर देश के बाहर से संकट है। चीन और पाकिस्तान ललचाई हुई नज़रो से हमारे देश की तरफ देख रहे हैं कि किस ढंग से हमारे देश के इलाके को वे अपने कब्जे में कर ले। इसलिये अगर कोई इस वक्त हिन्दुस्तान के सच्चे दोस्त है, तो ये अपोजीशन के लोग है। इसलिये बजाय, इसके कि यहा पर आपस मे वहस मुबाहिसा हो, बजाय इसके कि यहा पर सवाल जबाब हों और वह अखबारात मे छपे, मैं प्रधान मंत्री से कहूगा कि वे हमारे नेताओ को जो अपोजीशन मे बैठ हुये है, उनको अपने काफिडेंस मे ले और बैठ कर के उनके साथ बात करें। आज जो सीज फायर की बात चल रही है उसमे प्रधान मंत्री को अपोजीशन के नेताओं, को अपने काफिडेंस में लेना चाहिये। अगर वे उनको कांफिडेंस में लें, तो फिर मैं समझता हूं कि इस हाउस में किसी किस्म की बातें नही होंगी और न कोई बयान अखबारात मे जायेगा और फिर हमारा समूचा देश एक नज़र आयेगा हमारे दुश्मनों को, पाकिस्तान को और चीन को। मै बैक बेंचर हू, मुझे नही पता कि हमारे नेताओं से बातचीत हुई है या नही, मगर मुझे डाह्याभाई की देशभक्ति पर, श्री वाजपेयी की देशभक्ति पर, श्री सिन्हा और श्री भूपेश गुप्ता की देशभक्ति पर कोई शक नही है और मैं समझता हूं कि अगर इस वक्त हमारे नेता ऊंचा उठें और इनको कांफिडेस मे लें तो हर रोज जो सवाल जवाब होते है वह न हो और जो इस ढंग की बातें आती है कि कोई कहता है कि पाकिस्तान पर हमला कर दो, कोई कहता है कि लाहोर पर हमला कर दो, कोई कहता है कि सियालकोट पर हमला कर दो, वे न आवें। ये बातें अखबारात मे जाने वाली नही है। यह तो आपस मे बैठ कर के तय करना है कि क्या लाइन अख्तियार करना चाहिए। तो अगर हमारे नेता ऊचा उठेंगे और अपोजीशन को अपनी काफिडेस में लेंगे तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि हम चीन का भी और पाकिस्तान का भी मुकाबिला कर सकते हैं। इसलिये कर सकते है कि हम बिल्कुल एक दीवार की तरह इकट्ठे हो जाएंगे इस मिनिस्ट्री के साथ, मगर बदकिस्मती से हमारे नेताओ ने यह समझा है कि वे जो चाहें कर सकते है और हर रोज बयान देते है। उस बयान की वेल्यू क्या है? यही वैल्यू है जो कि मैंने पढ़ा कर आपको सुनाया है। इस वक्त जरूरत यह है कि हमारे जो नेता है वे बहुत कम बयान दें। जब हमारे राष्ट्रपति बरदोली में गये तब उन्होने एक बयान दिया था, बड़ा शानदार बयान था, वह मैं इस हाउस के सामने पढ कर सुनाना चाहता हूं:

"Indian reverses in NEFA should be regarded as a matter of sorrow, shame and humiliation. We have to retrieve our lost prestige. India's

[श्री जगत नारायण]

freedom, security and honour are the things which are endangered today. The qualities of courage, discipline and organised determination for which Sardar Vallabhbhai Patel stood are required of the nation now to overcome the shame."

आज जरूरत है हमें सरदार पटेल की, पटेल जैसे लीडर की, जोकि आज देश को आगे ले जा सके। इसके मुताल्लिक वहां हमारे राष्ट्रपति ने आगे कहा :

"Sardar Patel was a man of few words, but of firm unequivocal tones and was one who gave expression to the voice of the nation which nobody could mistake or misunderstand. One knew when he spoke what he meant and what he stood for. In a democracy we govern by talking. When we talk, therefore, we have to be precise, clear and consistent and must not go about saying things which have to be explained a hundred times later".

तो राष्ट्रपति जी ने क्या कहा ? उन्होंने कहा कि आज जरूरत नहीं है कि बहुत लम्बे चौड़े बयान दिये जांय। आज जरूरत नहीं है कि हम रोज चैलेंज करते रहें कि यह कर देंगे वह कर देंगे। जो करना हो वह करिए। आप बैठिए अपोजीशन के साथ, अपने कांग्रेस के नेताओं को बिठलाइये, और यह हो सकता है कि मिलिटरी के बड़े बड़े अफसरों को बिठाइए डिफेंस मिनिस्टर को बिठाइए, उनको एक कमरे में बन्द कर दीजिए, दो दिन बन्द रहें और फिर जो करना हो वह कीजिए। आज जो यह सब सिलसिला चल रहा है कि हम यहां जा रहे है, वहां जा रहे हैं, आज शास्त्री जी रशिया जा रहे हैं या और जगह जा रहे है तो वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, जिस वक्त देश पर इतना संकट हो तब बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां बैठिए और यहां बैठ कर सलाह मशविरा कीजिए और एक मन बना कर जो कदम उठाना हो वह उठाइए। पिछले दिनों शास्त्री जी ने स्टेटमेंट दिया। मैं उस वक्त जालंधर में था। श्री शास्त्री जी के बयान से लोगों के दिल बल्लियों उछले कि आज हमारी हकूमत जो है वह भी कुछ करने जा रही है। वहां पर एक अफवाह यह फैल गई कि हम लाहौर जा रहे हैं, लाहौर को आध घंटे में सर कर लेंगे लेकिन हुआ कुछ नहीं और लोगों का जो इनथ्यूजियाज्म था वह डैम्पेन हो गया। कहा कुछ जाता है, बड़े जोर के अल्फाज में कहा जाता है मगर जब अमल का मौका आता है तो ऐसे गुम सुम हो कर बैठ जाते हैं कि दुनिया हैरान हो जाती है।

वाइस चेयरमैन साहब, आज पाकिस्तान से हमें धक्का लगा है लेकिन मैं हूं, कल यहां पर एक सवाल हुआ था कि चाऊ एन लाई अफ्रीका या कहीं जा रहे थे तो उनका जहाज हिन्दुस्तान से गुजरा और कहा गया कि हमारा पाकिस्तान से मुआहिदा है कि उनके जहाज जा सकते हैं, मगर क्या हिन्दुस्तान का यह भी मुआहिदा है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान के मिलिटरी आफिसर्स और उसकी फौजें मशरिकी पाकिस्तान में हिन्दुस्तान के ऊपर से फ्लाई करके जायंगी। आज के अखबारात में यह छपा हुआ है। इसको पढ़ कर के दुःख होता है। आज हालत क्या है ? आज हालत यह है कि पाकिस्तान के स्पाइज़ बैठे हुए हैं, काश्मीर में बैठे हुए हैं, यहां दिल्ली में बैठे हुए हैं, जालंधर में बैठे हुए हैं, अमृतसर में बैठे हुए हैं और वे तमाम बातें अपने देश को पहुंचा रहे हैं। पिछले दिनों यहां पर एक फैसला किया, आल इंडिया रेडियो में कुछ हुआ और वह विदइन फिफ्टीन मिनिट्स पाकिस्तान के रेडियो से ब्राडकास्ट हुआ। अखबारात में यह भी छपा हुआ है। हमारी तो कोई चीज खुफिया नहीं रहती।

तो इस वक्त जरूरत क्या है सबसे ज्यादा ? सबसे पहले अगर कोई कदम हमारी सरकार को उठाना चाहिए तो यह उठाना चाहिए कि पाकिस्तान की इम्बैसी को बन्द करना चाहिए, चीन की इम्बैसी को बन्द करना चाहिए, उनको बन्द करके उन मुल्कों को

जवाब देना चाहिए कि हम भी एक जानदार मुल्क हैं, हम भी कोई कदम उठा सकते हैं, उसके बाद बातचीत होनी चाहिए अगर कोई बात हो तो। मगर सवाल इस वक्त यह पैदा होता है कि इस वक्त हम करना क्या चाहते हैं। तो वाइसचेयरमैन साहब, मैं यह समझता हूं कि सबसे पहले हमारे नेताओं को जो अपोजीशन के हैं उनको, मिल कर बैठ कर फैसला कर लेना है कि हम इस सदन में, न लोक सभा मे न राज्य सभा मे, इस किस्म के सवाल नही करेंगे जिससे कि देश को हानि पहुचती है। मुझे यकीन है कि हमारे नेता जो है वे यकीनन देश के हित के लिए तमाम बातें सुनेंगे बशर्ते कि आपका एटीट्यूड रीजनेबिल हो और उनको पूरे कान्फिडेंस मे लेने के लिए तैयार हो। दूसरी चीज यह है कि इम्बैसीज को फौरन बन्द कीजिए। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वहा से खबरे आ रही है कि यह हो रहा है, वह हो रहा है। पाकिस्तान की आर्मी कितनी है? हिन्दुस्तान की आर्मी पाकिस्तान से पांच गुना ज्यादा है। क्या बात है कि हमारी आर्मी आज बार्डर पर नही बैठी हुई है, हमने वहां पुलिस के आदमी बैठाए हुए है जिनको भर्ती हुए छ महीने, साल भर या डेढ़ साल हुआ है। क्यो नही वहा बाकायदा फौज भेजी जाय जब कि आपकी फौज की तादाद पाकिस्तान से पाच गुनी है। आप अपने बार्डर को उसी तरह से डिफेंड करे और वहां उसी ढंग से करे कि पाकिस्तान के लोगों को मालूम हो कि हिन्दुस्तान की जो फौज है वह पूरी तरह से सारे बार्डर पर बैठी है और अगर कही उन्होने जरा आगे बढने की कोशिश की तो गोलियों की दनादन मे वह खत्म हो जाएंगे।

आपका हाथ घंटी पर है। मै आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इस वक्त इतना ही कहूंगा कि हमारी सरकार को ऊंचा उठना चाहिए और ऊंचा उठ कर अपोजीशन को कांफिडेंस मे लेकर आगे बढ़ना चाहिए और इस किस्म का कोई मुआहिदा नही करना चाहिए जिस मुआहिदे से कि यहां जो संकल्प किया है वह जाता रहे। यहा पर जो करते रहे उसके खिलाफ कोई मुआहिदा किया तो याद रखिए कि देश आपको कभी माफ नहीं करेगा, आने वाला जमाना कभी माफ नही करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सब से पहले मै सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे मे आकृष्ट करना चाहता हू। तीन पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो गई परन्तु इस देश का सब से बडी जन सख्या वाला प्रदेश जिसकी जन संख्या 8 करोड़ है सब बातो मे आज पीछे है। बिजली, शक्ति, जो आज सभी विकास का आधार और साधन है, उसकी खपत उत्तर प्रदेश में सभी प्रदेशो मे कम है। आज इस देश के समस्त राज्यो मे से, सम्भवत: जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर, बिजली की खपत सब से कम उत्तर प्रदेश की है। केवल 37 किलोवाट है जब कि दिल्ली की 224, बंगाल की 137, महाराष्ट्र की 119, मद्रास की 110, पंजाब की 105, गुजरात की 92, मैसूर की 84, उडीसा की 82, केरल की 60, बिहार की 58 और मध्य प्रदेश की 49 है और आसाम की 43 है। इस प्रकार बिजली के उत्पादन के लिए बार बार योजना बनाते हुए भी उत्तर प्रदेश को केन्द्र की सरकार से पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओ मे वह आवश्यक वित्तीय सहायता नही मिल सकी जिसके आधार पर वह अपने प्रदेश की कृषि व्यवस्था को भी और उद्योग व्यवस्था को भी सम्हाल सकता। जिसका परिणाम यह रहा है कि वह प्रदेश जो हमारे देश का एक खलिहान हो सकता है, जिसकी विशाल

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

भूमि अत्यन्त उर्वर भी है, खाद के लिए और पानी के लिए तरस रहा है और जिसका परिणाम यह हो गया है कि उत्तर प्रदेश अपने प्रदेश में बसने वालो को न अब रोटी दे सकता है, न धंधा दे सकता है ।

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

उद्योगो का भी वितरण पिछली पंचवर्षीय योजनाओ मे, जो बुनियादी उद्योग देश मे कायम हुए है उनका, कुछ इस प्रकार से हुआ है कि उत्तर प्रदेश उससे सर्वथा वंचित रहा है । हमे अब यह जान कर कुछ संतोष हो रहा है कि सरकार का ध्यान अगली चतुर्थ पंचवर्षीय योजना मे उत्तर प्रदेश की तरफ, जहा तक उद्योगो के वितरण का प्रश्न है, कुछ जा रहा है । मैं आशा करता हू कि आगामी वर्षो मे उत्तर प्रदेश की तरफ केन्द्र की सरकार उसी प्रकार से ध्यान देगी जिस प्रकार से कि हृदय का ध्यान देना सारे शरीर के लिए आवश्यक होता है । सुनियोजित अर्थ व्यवस्था मे आर्थिक विकास के लिये वित्तीय साधनो पर केन्द्र का अधिकार होना है । विदेशी मुद्रा की व्यवस्था भी केन्द्र ही करता है । अतएव न केवल यह आवश्यक है अपितु परम वाछनीय है कि भविष्य मे केन्द्र सभी अर्थ व्यवस्था को इस प्रकार से सोचे और नियोजित करे ताकि देश का कोई कोना एकदम आगे बढ़ जाय और दूसरा भाग एकदम पिछडा रह जाय, यह परिस्थिति न हो ।

महोदया, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे जो हमारे दूतावास हैं उनका कार्य पिछले, दस पन्द्रह वर्षों में जैसे भी रहा हो लेकिन पिछले दो तीन वर्षों से, जैसा कि देखने में आता है, जो समय की आवश्यकता है उस की पूर्ति उनसे नहीं हो रही है । चीन के हमले के समय हमने देखा और पाकिस्तान के हमले के साथ भी हम देख रहे हैं कि सारे वाह्य जगत में कहीं से भी ऐसी झलक नही दिखायी पड़ती कि हमारे दूतावास इस बात में सफल हो रहे हैं कि आज पाकिस्तान हमारे ऊपर जो हमला कर रहा है, और उस का हमला हुआ है, उसकी सही सही तसवीर हमारे विदेशों में अपने जो दूतावास हैं उसको दिखाने में वे समर्थ हो रहे हैं । उनकी कार्यविधि भी ऐसी है कि जो हमारे प्रवासी भारतीय है उनको भी उनसे कोई सहायता नही मिलती है । हमारे जितने भी दूतावासों के कार्य उनके संचालनकर्ता हमारी सेवाओं के लोग हैं जिनको कि देश की राजनीतिक परिस्थिति और लक्ष्य का उतना ध्यान नही रहता, जितना अपने सरकारी दफ्तरों को चलाने का ध्यान रहता है । इस अवसर पर मैं समझता हूं कि इस समय जो देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है वह यह है कि संसार में इस बात की जानकारी हो कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का यह जो झगड़ा है यह सीमा का विवाद नहीं है अपितु पाकिस्तान ने सीधे सीधे भारत की धरती पर हमला किया है । यदि ऐसा ज्ञान होता तो बहुत से देश जो हमले के, आक्रमण के विरुद्ध हैं, वे तो कम से कम अपनी आवाज तो उठाते । आज हमारी वैदेशिक नीति यह है कि आज कोई हमारे मित्र दिखायी नही देते और यहा तक कि जो हमारे मित्र रहे है, जिनके समय में हम उनके काम मे आए हैं, वे भी संशय मे हैं कि हम सही पर है कि नहीं ।

प्रतिरक्षा का प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है । इस सम्बन्ध में हमे अपने देश की प्रतिरक्षा के लिये अपने देश के सारे इतिहास को मद्देनजर रखते हुए, हमेशा के लिये तय करना होगा कि हमारी क्या नीति है । पिछले तीन वर्षों से हमारे देश मे इमरजेन्सी की स्थिति चल रही है । इमरजेन्सी की स्थिति का अर्थ यह होता है कि देश चोकन्ना और तैयार रहे । न केवल इमरजेन्सी चीन के मामले में थी, अपितु हमारी सीमाओ पर पन्द्रह वर्षों से पाकिस्तान से हमारा "सीज फायर" है, जिस का अर्थ यह है कि पाकिस्तान से हम लडाई पर हैं—केवल अस्थायी संधि है । चीन से भी हमारा "सीज फायर" है,

जिसका अर्थ है हम उससे लडाई पर हैं–केवल अस्थायी संधि है । अतएव किसी सीमा पर, किसी कोने पर, कोई शत्रु हमारे ऊपर हमला करे और हम कहें वह हमारा वल्लरेब्ल पोइन्ट था, कमजोर जगह थी, इसलिये दुश्मन चला आया, इससे देश को संतोष नहीं हो सकता, इससे देश का आत्मबल गिरता है, सेना का आत्मबल गिरता है और संसार के देशों में भी हमारा सम्मान गिरता है । इतना बड़ा देश–47 करोड़ की जनसंख्या वाला महान् देश–जिस सरकार और नेतृत्व के पीछे खड़ा हो, उसका इस देश और जनता के प्रति एक महान दायित्व है । इस अवसर पर मुझे तुलसीदास का एक पद याद आता है जिसमें उन्होंने कहा है : "टेढ़ जांन शंका सब काहू" रहीम ने भी कहा है :

"रहिमन ऐंढ़ न छोड़िए, जंह तंह ऐंड़ बिकाय
बिना ऐंड़ का चारवा, खुरपी लादा जाय ।"

जो भारत सरकार सह अस्तित्व और शांत का नारा लगाती थी, जैसे उसने ठेका ले लिया है संसार भर को शांति और संतोष देने का । और अपने देश में हमले का आह्वान करे, जब चीन ने हमारे ऊपर हमला करने के बाद अणुबम बनाया तब भी हमने तय किया कि हम अणुबम नही बनायेंगे । अणुबम की आवश्यकता इसलिये नहीं कि हम दुश्मन पर अणुबम का प्रहार करेंगे बल्कि इसलिये है कि हमारी सेना को और देशवासियों को आत्मविश्वास हो कि शत्रु के पास जो अस्त्र शस्त्र हैं उसके मुकाबले में हमारे पास भी अस्त्र शस्त्र हैं ताकि युद्ध में हमें इस बात की निश्चिन्तता हो कि अंतिम विजय हमारी रहेगी । यदि हमारे मन में यह भय उत्पन्न हो जाय कि हमारे पास ऐसा अस्त्र ही नहीं है तो हम कितने ही बलिदान करें, कितनी भी कुर्बानी करें, कितना ही सेना का रक्त बहा दें लेकिन दुश्मन के पास ऐसा हथियार हो जो वह इस्तेमाल करेगा तो हमारी पराजय होगी–इससे सेना का मनोबल गिरता है, देश की जनता का मनोबल गिरता है जो अपना सब कुछ दे कर, अपना तन, मन, धन देकर, देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिये तैयार है उसका मनोबल गिरता है. और सबसे अधिक मनोबल गिरता है देश के आस पास जो पड़ौसी है उनका । आज एशिया और अफ्रीका का कोई देश इस बात का विश्वास नहीं रख रहा है कि सन् 1962 के बाद भारत में वह शक्ति और सामर्थ्य है कि वह अपनी रक्षा कर सकता है । चीन की सेनाएँ हमारे देश में घुस सकती है, यहा तक कि पाकिस्तान की भी सेनायें घुसी चली आ रही है । क्षोभ होता है जानकर कि सन् 1956 से इस बात की जानकारी थी कि पाकिस्तान की कुदृष्टि कच्छ के रण पर है, सन् 1956 से जानकारी थी कि कच्छ की सीमा कमजोर है, सन् 1956 से जानकारी थी कि वहां हमारे यातायात के साधन नही है । सरकार को उधर ध्यान देना था । जब हमने अक्साई चिन पर चीन का प्रवेश होते देखा था, उसी समय हमेशा के लिये सबक सीख लेना चाहिये था । एक ही बार सबक हमेशा के लिये सीखना चाहिये था । बार बार गलती को दोहराना किसी राष्ट्र के जीवन में कभी भी क्षम्य नहीं हो सकता । महोदया, मैं इस बात को मानता हूं कि : Constant vigilance is the price of freedom and over-preparedness for war is the greatest deterrent against it. हम चाहते हैं, संसार में युद्ध न हो परन्तु यदि हम कमजोर रहेंगे तो युद्ध को हम रोक नहीं सकते । हम चाहते है कि हमारे ऊपर कोई हमला न करे । परन्तु हम बेखबर रहेंगे तो हमले को रोक नहीं सकते हैं । मैं देखता यह हूं कि भारत सरकार पिछले तीन वर्षों मे इमरजेन्सी की स्थिति में रहते हुए भी यह हो कैसे गया कि हमारे किसी कोने पर ऐसा दुश्मन हमला कर रहा है जो पन्द्रह सालों से हमारा दुश्मन है, जिसका इरादा हमको मालूम है, जिसने नाकिस इरादे से हम कभी बेखबर नहीं हो सकते । क्या हम यह सोच सकते हैं कि हम देश की जनता को

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

बताए कि वहा पर दलदल है, वहा पर पानी है, सडक नही है, वहा हमारी सेना नही पहुंच सकती, केवल पुलिस रह सकती है। इस देश का कोई व्यक्ति यह सुनने के लिये तैयार नहीं है। मान्यवर, हमारा उत्तरदायित्व है, जो जनता के बीच मे जाते है, उनकी बातें सुनते है--उनके मनोबल को कायम रखने से पहले हमारा उत्तरदायित्व यह है कि हम सरकार को प्रहरी कुत्ते की तरह बताये कि आज जो जनता आप के पीछे हिमालय की दीवार की तरह खडी है उसका मनोबल ढीला हो रहा है आप की कमजोरी से, आपके ढीलेपन से, आप के सीधेपन से, आपके बेखबर रहने से। इस सरकार के लिये इस समय यह कहना कि पाकिस्तान ने अचम्भे मे हमला कर दिया कोई मच्छर तो जरूर गुनगुनाकर काटने आता किन कोई शत्रु हमला नही करता। गाना गाकर, ढोल बजा कर, न वह आपको बता कर हमला करेगा, न वह जगह बताएगा। आज जरूरत इस बात की है कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया हमारी कमजोर जगह पर तो पाकिस्तान की जो दसियो जगह कमजोर थी वहा हमारा हमला होना चाहिये था सीज फायर का प्रश्न हमारे लिये हमेशा के लिये खतरनाक है, जिस तरह से लद्दाख मे और दूसरी जगहो मे चीन अपनी फौजे लेकर घुस आया उसी तरह से पाकिस्तानी फौजें भी काश्मीर में घुस आयी थी। काश्मीर मे जहां पाकिस्तान की फौजे आई वहां सीज फायर के पन्द्रह वर्षों बाद आज भी पाकिस्तान का कब्जा है। सीज फायर के बाद एक इच भी जमीन अगर पाकिस्तान के कब्जे मे है तो इस तरह से हमेशा जब तक सन्धि वार्ता चलती रहेगी उसी के कब्जे में रहेगी और हमेशा देश की दुर्दशा होती रहेगी। अगर आप समझते है कि केवल हिन्दुस्तान का उत्तरदायित्व यह है कि संसार मे युद्ध का विस्तार न हो, तो फिर हिन्दुस्तान की सीमाओं को आरक्षित छोड़ देना चाहिये, दुश्मन की फौज़े आने दीजिए, संसार मे "वसुधैव कुटुम्बकम्" का पाठ जो संसद् भवन के ऊपर लिखा हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि सारे संसार को अपना घर समझो, आप किसी को दुश्मन न समझे। लेकिन आप इस बात को समझें कि जब आपका दरवाजा कमजोर होगा तभी धक्का दे कर चोर घुस आएगा। हम इस बात का संकल्प करें कि हम दुश्मन को हटा कर छोड़ेगे। तीन वर्ष पहले हमने ऐसा सकल्प किया था लेकिन उसकी तरफ हमारा कदम नही उठा। अब की तीसरी बार फिर हमारे ऊपर हमला हुआ है और फिर हमने संकल्प किया--इस ससद् का संकल्प, इस देश की जनता के कंठ-कंठ का संकल्प है, केवल इस सदन का संकल्प नही है, केवल ससद् सदस्यो का संकल्प नही है--और इस देश की सरकार को इस बात का आभास होना चाहिये, विश्वास होना चाहिये कि पत्थर के चट्टान की तरह देश की ४७ करोड़ जनता उसके पीछे खड़ी है। इस देश का मनोबल उठाने के लिये उसे उचित कदम उठाने चाहियें, आज हिन्दुस्तान की एक एक जनता दुखी है क्रुद्ध है यह जानकर कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को मौके का जवाब नही दिया।

महोदया, मै आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि वह देश जिसने कि हमारे पास सन्धि का प्रस्ताव भेजा है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हम आज चाहे भले ही कुछ न कहें लेकिन उस पर हमे भरोसा नही है। पाकिस्तान ने अमेरिका से जितनी फौजी सहायता ली है वह कम्युनिस्ट चीन से लड़ने के लिये ली है, यह मानने की गलती न करें। सारा शस्त्र बल उसने हिन्दुस्तान से लड़ने के लिये लिया है और अमेरिका ने, मै यह कहना चाहता हूं, कि यह जानते हुए िया है कि किसी भी साबरेन देश पर कोई काबू नही रह सकता कि उसके हाथ मे आए हुए हथियार को इस्तेमाल न करने दे। मैं जानता हूं अमेरिका कुछ भी करे लेकिन अमेरिका पाकिस्तान से हथियार वापस नहीं ले सकता और पाकिस्तान के सैनिकों को उन हथियारों का इस्तेमाल करने

से रोकने की कोई शक्ति उसमे नहीं है । तो हम उसको चाहे कितना भी कहें वे कर क्या सकते हैं यह सोचना होगा ।

हमको यह समझना चाहिये महोदया, कि हिन्दुस्तान की स्वाधीनता की रक्षा का उत्तरदायित्व हिन्दुस्तान की जनता और हिन्दुस्तान की सरकार पर है । हिन्दुस्तान के वैज्ञानिक ही हिन्दुस्तान की रक्षा के लिये शस्त्र तैयार करेंगे, हिन्दुस्तान की जनता ही इस हिन्दुस्तान की रक्षा के लिये अर्थ दान करेगी, हिन्दुस्तान के जवान ही हिन्दुस्तान की रक्षा के लिये अपने जीवन का बलिदान करेंगे । यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिक हमारे लिये अस्त्र बनाएं, दूसरे देशों के करदाता हमे अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिये पैसा दें और दूसरे देशो के जवान आकर हमारी सीमा की रक्षा करे, यह सम्भव नही है, यह विडम्बना है, हम भले ही कहे कि हम अणुबम नही भी बनाते लेकिन यह ऐलान करना कि हम अपने हाथ मे ऐसा हथियार नही रखेंगे, जिससे दुश्मन की पराजय हो यह दुश्मन को हमेशा के लिये आश्वस्त कर देना है कि जब मौका आएगा हमे पहले वह पराभव कर सकते हैं, विजय कर सकते है। महोदया, पूर्वग्रह, किसी व्यक्ति के लिये आदर्श हो सकता है लेकिन स्वाधीनता की रक्षा, देश की सीमा की रक्षा को किसी व्यक्ति या किसी पार्टी या किसी सरकार के पूर्वग्रह के आश्रित नही कर सकते, इसके लिये हमे हमेशा समय के अनुसार कदम उठाना पड़ेगा । हमारा ध्येय नान एलाइनमेट है लेकिन आज उसका परिस्थिति यह हो गई है कि ससार मे कोई भी देश हमारा मित्र नही दिखलाई पड़ता है । अगर नान एलाइनमेट का अर्थ यही है कि जब हम सत्य पर है, जब हम न्याय पर है, जब हम औचित्य पर है, तब कोई भी हमारे हक मे आवाज उठाने वाला नही है, तो हम इसको कब तक कायम रख सकते है ? इस देश की स्वाधीनता को खोकर कोई पूर्वाग्रह इस देश की सरकार को जीवित नही रख सकता है. यह मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

महोदया, मैं इस सदन का ज्यादा समय नही लेना चाहता हूं । आज हमारे देश की जिस तरह की स्थिति है उसमे हम सब लोगो को संयम से काम लेना चाहिये । इसलिये मै सरकार को यह सुझाव नही देता कि वह कल क्या कदम उठाये और क्या करे । मैं सरकार की इस बात की भी निन्दा नही करता कि वह इतनी बेखबर क्यो रही । लेकिन इस देश के कोने कोने मे जनता मे क्रोध की भावना भरी पड़ी हुई है कि इस तरह का अपमान हमारे देश का क्यों हुआ और सरकार ने उसका बदला क्यो नही लिया । आप देश की जनता को यह दिखलाइये कि उसके दिये हुए कर का और विश्वास का आप ठीक उपयोग कर रहे है या नही ? अगर आपने देशकी जनता को यह नही दिखलाया कि जो सेना पर खर्च किया गया वह देश की रक्षा के लिये है । अगर आप देश की जनता को यह नही समझा सकते है कि आप देश की रक्षा के लिए समर्थ है, तब आप इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं । आज देश में मानसिक संकट की स्थिति है और और उसका मनोबल खो रहा है । आज पाकिस्तान जैसे छोटे देश ने हमारे देश के ऊपर हमला कर दिया और हमारी जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया और हिन्दुस्तान को वह शक्ति नही है कि वह अपनी जमीन को वापस ले सके। हम यह इसलिए नही करते कि हमको डर है कि कही विश्व युद्ध न हो जाय । हम इस बात से डरते है कि कही टोटल युद्ध हो गया तो यह हिन्दुस्तान के लिए एक खतरनाक बात होगी । लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब यह बात हमारे लिए खतरनाक होगी तो क्या पाकिस्तान के लिए खतरनाक नहीं होगी ? अगर इस तरह की बात होती है तो लड़ते लड़ते मर जाना अच्छा है बनिस्बत जीवित रहते स्वाधीनता पर हमला होते देना और यह हर एक स्वाभिमानी देश का कर्त्तव्य है । मुझे क्षोभ होता है कि स्वाधीन देश के जीवन को आत्मबल देने वाली सरकार है, लेकिन आज वह सरकार देश की स्वाधीनता के लिए जीवन की बलि देने वाले

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]
नवयुवकों को आगे नही कर रही है । यह हमारी दुर्दशा है और यह स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें सरकार का समर्थन यह कहकर कर दे कि आपका कदम तो पीछे उठता जाय, एक पोस्ट छोड़ते जायें, दूसरी पोस्ट से हटते जायें और यह कह दें कि मिलिट्री का फैसला हुआ है । ये सब चीजें हमारे देश के मनोबल को बढ़ाने वाली नही है । देश की जनता नही समझती है कि इस तरह की स्थिति क्यों हुई है और आप तैयार क्यो नही हैं ? खासकर ऐसी हालत मे जैसाकि बहिन मनिबेन ने बतलाया और भी कई सदस्यो ने बतलाया कि पिछले कई महीनो मे, कई वर्षों मे, सरकार को इस बात की चेतावनी मिल रही है लेकिन वह हमेशा ही दब जाती है । हमारी सरकार अपने हाथो से देश की सीमाओ को खो रही है और इस तरह की स्थिति बहुत दिनो तक चलने वाली नही है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हू कि प्रतिरक्षा के प्रश्न पर हमको फिर से विचार करना होगा और इस देश की समस्त सीमाओ की रक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय सेना के जिम्मे रखना होगा । इस मामले को प्रादेशिक पुलिस के हाथ मे नही रखना होगा । अगर हमने ऐसा किया तो हम हमेशा हर जगह अपने को तैयार नहीं पायेंगे । और फिर हमे इस देश की जनता का कोप भोजन बनना पड़ेगा तथा इस सरकार के पैर लड़खड़ायेंगे ।

मैं इस निवेदन के साथ अपना भाषण समाप्त करता हू ।

ANNOUNCEMENT *RE* STATEMENT ON KUTCH BORDER SITUATION

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform the House that Government would make a statement on the Kutch border situation at 6 P.M. today Therefore the House will sit till that time.

THE APPROPRIATION (NO 2) BILL, 1965—*continued.*

श्री देवी सिंह (राजस्थान) . उपसभापति महोदया, आज हमारा देश एक बहुत ही महत्वपूर्ण सकट से गुजर रहा है और आज हमारे देश के सामने बड़ी भीषण परिस्थिति आई हुई है । हमारे देश के दोनो तरफ से हमला हो रहा है । बाहर की ओर से चीन और पाकिस्तान का हमला हो रहा है और भीतर भ्रष्टाचार और अनाज की कमी तथा भाषा का प्रश्न आदि कई समस्यायें है । बाहर की तरफ से हमारे देश के ऊपर जो हमला हुआ और उसका मुकाबला हमारे जवान किस तरह से कर रहे है उसकी सराहना किये बिना नही रहा जा सकता है । परन्तु यह दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार की जो नीति है उस के कारण हमारी सेना के जवानो को निराशा हो रही है और वह बढती ही जा रही है । चीन ने जब हमारे ऊपर हमला किया तो हमारे देश की सरकार की गलत नीति के कारण नीचा देखना पड़ा । हमारे बहुत से जवानो ने अपनी बलि दी और उसके बाद सरकार ने देश का कुछ इलाका चीन के कब्जे मे दे दिया । उस वक्त यह कहा गया कि चीन एक बड़ा देश है, उसके पास बहुत बड़ी शक्ति और सेना है और हमारी सेना उस का मुकाबला करने के लिए समर्थ नही है । आज वही चीज पाकिस्तान जैसे छोटे देश के साथ दोहराई जा रही है । आज हम यह देख रहे है कि पाकिस्तान जैसे छोटे देश के मुकाबले मे हमारी सेना को अपनी पोस्ट खाली करनी पड़ रही है । हमारी सरकार की कमजोर नीति के कारण कंजरकोट हमारे हाथ से चला गया जिसकी वजह से हमारी सेना के मनोबल पर बहुत खराब असर हुआ है । इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि देश की रक्षा करने की आपकी जो पालिसी है उसको बदलना चाहिये । आज सरकार के पास बहुमत है इसलिए वह इस तरह की पालिसी चल रही है और